

₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

जुलाई 2025

DARAS
M R I

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

हत्याओं का सिलसिला जारी

सरकार के विकास पर
आपराधिक वारदात भारी!

मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण पर
विपक्ष क्यों कर रहा बवाल?

RNI NO- BIEHN/2006/18181, DWP NO-129888, POSTAL REG. NO.- PS-85

जन-जन की आवाज है केवल सच



Kewalachlive.in

वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ



आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं की सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा



www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

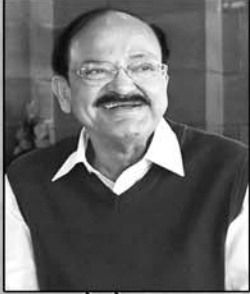
-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,

कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605



जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ



एम. वेंकैया नायडू
01 जुलाई 1949



अखिलेश यादव
01 जुलाई 1973



हरभजन सिंह
03 जुलाई 1980



स्व० रामविलास पासवान
05 जुलाई 1946



एम.एस. धोनी
07 जुलाई 1981



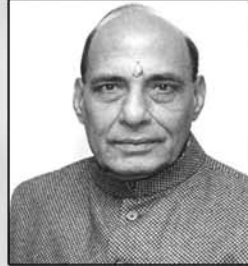
केलास खेर
07 जुलाई 1973



सौरभ गांगुली
08 जुलाई 1972



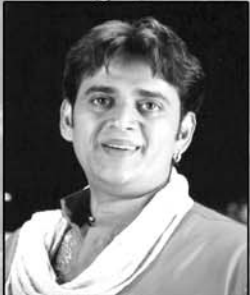
सुखवीर सिंह बादल
9 जुलाई 1962



राजनाथ सिंह
10 जुलाई 1951



सुनिल गवास्कर
10 जुलाई 1949



रवि किशन
17 जुलाई 1971



प्रियंका चोपड़ा
18 जुलाई 1982



नसरुद्दीन शाह
20 जुलाई 1950



मल्लिकार्जुन खड़गे
21 जुलाई 1942



स्व० अनंत कुमार
22 जुलाई 1959



हिमेश रेशमिया
23 जुलाई 1973



पंकज आडवाणी
24 जुलाई 1985



उद्धव ठाकरे
27 जुलाई 1960



संजय दत्त
29 जुलाई 1959



सोनू निगम
30 जुलाई 1973

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-

East Ashok, Nagar, House
No.-28/14, Road No.-14,
kankarbagh, Patna- 8000 20
(Bihar) Mob.-09431073769

E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-

Vaishnavi Enclave,
Second Floor, Flat No. 2B,
Near-firing range,
Bariatu Road, Ranchi- 834001

E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-

Sanjay Kumar Sinha,
A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla
Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991,
09955077308

E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-

Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue,
Near- md. Ali Park,
Kolkata- 700073
(West Bengal)
Mob.- 09433567880
09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
	Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
	Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
	Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
	Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
	Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
	Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
	Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000
W B &	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	
	Inner Page	60,000/-	35,000/-	

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेबसाइट www.kewalsach.com के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेबसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)



बिहार का कौन होगा सरदार

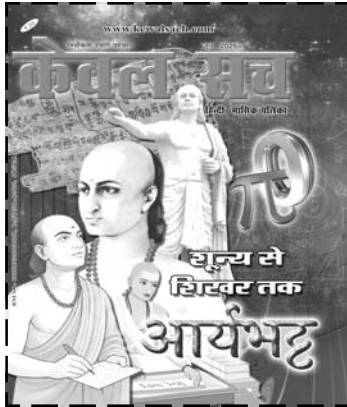
बि

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की डुगडुगी बज चुकी है सभी पार्टियां 2025 से 2030 तक सरदार बनने के लिए हर जुगाड़ को सेट कर रही है। विभिन्न पार्टियों का प्रचार कर चुके प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी जन सुराज बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान के बाद एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा दी है। एक तरफ लालू यादव का माय समीकरण तो नीतीश कुमार का विकास समीकरण तो तीसरी तरफ जनसुराज का दावा करना की सरदार तो जन्मा इस बार मुझे ही चुनेगी की चर्चा सूबे के हर गांव में हो रहा है। आवाम के बीच चर्चा है कि 10 सीट पाकर जनसुराज सत्ता के सिंहासन पर पहुंच सकती है लेकिन प्रशांत किशोर 143 सीट से कम आने पर हार स्वीकार करेंगी की बात को लोग मजाक में ले रहे हैं। 15 साल बनाम 20 साल (05 साल सत्ता का अदला-बदली) की सत्ता के सिंहासन में नीतीश कुमार का पलड़ा आज भी भारी लगता है क्योंकि बिहार वास्तव में बदल रहा है और भ्रष्टाचार के साथ ही सही पर बिहार का विकास हो रहा है इसको झुठलाया नहीं जा सकता। बिहार बदलाव यात्रा करके जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करने में प्रशांत किशोर भले ही कामयाब हों परन्तु माय समीकरण का जोड़ को तोड़ आज भी मुश्किल भरा है। बिहार अपने लिए किसको अगला सरदार चुनेगी यह तो भविष्य में गर्भ में है पर नीतीश कुमार का विकल्प आसान नहीं है। वोटर लिस्ट मामले को जनता कितना महत्व देती है सरदार बनने में...

ब्रजेश मिश्र, संपादक

8340360961, 9431073769

हार में बहार है, नीतीश कुमार है कि स्लोगन को बदलना आज भी आसान नहीं है। तेजी से विकसित होते बिहार के नेता नीतीश कुमार का विकल्प खोजने में सहयोगी भाजपा भी धर्मसंकट में है तो विपक्ष के तेजस्वी आज भी किसी प्रकार नीतीश कुमार के साथ गठजोड़ हो जाये उसकी जुगाड़ में लगे रहते हैं। वक्फ बोर्ड का मामला, एनआरसी-सीए, एसआईआर जैसे गंभीर विषयों को लेकर तेजस्वी यादव सत्तारूढ़ दल को चुनावी मैदान में परास्त करने के लिए किसी भी हद तक जाकर बयान तो दे रहे हैं परन्तु यह भी डर खाये जा रहा है कि उनके वोटर का नाम ही मतदान लिस्ट से बाहर हो जाये। पिछले एक वर्षों में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आवाम भी भय के साये में जी रही है लेकिन 15 साल के जंगलराज की कारनामे की वजह से उनका मिजाज अभी भी इंडिया गठबंधन की तरफ जाता नहीं दिख रहा है और सिवान के बेकसूर अजय यादव की हत्या से नाराज यादव युवाओं का गुस्से का मुकाबला करना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं होगा। बिहार में बढ़ते अफसरशाही और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष गंभीर नहीं दिखता जितना वह मुसलमानों का साथ कैसे मिले उसके जुगाड़ में मशगूल है। भाजपा+जदयू+अन्य के भीतर भी कभी भी विश्वासघात की घटना घट सकती है और इसी बीच में लगातार इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव पर जिस प्रकार जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर हमलावर है उससे तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि राजद का लालटेन में रौशनी कम करने में वह सफल हो सकते हैं। एक तरफ राजद नेता तेजस्वी यादव, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कूटनीति का जवाब देने में लगे हैं तो घर के भीतर ही बगावत कर चुके तेजप्रताप यादव का मुकाबला करना आसान नहीं होगा और कहीं वास्तव में एनडीए ने तेजप्रताप यादव को मुहआ से चुनावी मैदान में उतारकर उनको स्टार प्रचारक बना दे तो फिर एक तरफ प्रशांत किशोर तो दूसरी तरफ तेजप्रताप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नासूर न बन जाये। जनता बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार से उब चुकी है क्योंकि अपने ही जमीन का मोटेशन में सीओ एवं कर्मचारी को लाखों का भेंट चढ़ाना पड़ रहा है, साथ ही हर विभाग में घोटाले की गंध का खुलासा खुद सरकार की एजेंसी कर रही है। चारा घोटाले का हवाला देकर लगभग 35 साल से पक्ष-विपक्ष की राजनीतिक बाजार गर्म है लेकिन लगभग 70 हजार करोड़ की हेरा-फेरी का मामला जनता के दिमाग में सेट करने में विपक्ष कामयाब नहीं दिखता। जिस प्रकार बिहार के सदन में शब्दों की मर्यादा को ताड़ताड़ किया जा रहा है उससे तो यह साफ हो चुका है कि बिहार की राजनीति में काबिल राजनेताओं का घोर संकट है और 21वीं सदी में भी किसी को माय समीकरण पर भरोसा है तो किसी को जय श्रीराम पर। बिहार में जनसुराज के प्रशांत किशोर को देश का दूसरा केजरीवाल बताने में भी लोग संकोच नहीं कर रहे हैं। विभिन्न दलों के नाराज एवं महत्वकांक्षा पूरा नहीं होने की वजह से इधर-उधर भटक रहे नेताओं को जनसुराज में शामिल कराकर सत्ता का स्थानांतरण कराने की मंशा बहुत ज्यादा कारगर होती नहीं दिख रही है वहीं पप्पु यादव, कन्हैया कुमार का अस्तित्व भी खतरे में जाता दिख रहा है। भारत की अन्य राजनीति दलों की पूछ बिहार में नगण्य ही दिख रहा है। बिहार का सरदार बनना आसान नहीं है क्योंकि यहां की जनता एक बार दिल में बैठा लेती है तो उसको कई दशकों तक उसपर भरोसा करती है और यही कारण है की 1947 की आजादी के आधा समय लालू एवं नीतीश ने काट लिया है। बिहार की जनता ने दोनों के कार्यकाल को बहुत नजदीक से देखा है और ऐसे में नीतीश कुमार के सपने को पंख देने का काम कर रहे पीएम मोदी का मुकाबला आसान नहीं है। बंगलादेशी एवं रोहंगिया के मुद्दे को जितना प्रचार तेजस्वी और ममता कर रही हैं उसका जवाब गोलबंद होकर हिन्दू वोटर्स ने दिया तो फिर 2025 से 2030 तक का सरदार एनडीए को होगा, इसको लिखने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।



जून 2025



हमारा ई-मेल

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

मिशन 2027

ब्रजेश जी,

वर्ष 2027 में उत्तरप्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है लेकिन तैयारी अभी से शुरू है। जून 2025 अंक में पत्रकार अजय कुमार ने “2027 का सियासी महाकुंभ” अपने आलेख में भाजपा एवं समाजवादी पार्टी की रणनीति के साथ-साथ अन्य दलों की भूमिका पर भी कारगर जानकारी पाठकों को दी है। संजय सक्सेना ने “बिहार में मोदी के हनुमान खुद बनना चाहते हैं राम” अपनी खबर में बिहार चुनाव पर सटीक समीक्षा की है। अब बिहार चुनाव का परिणाम ही बतायेगा की सच क्या है। अच्छी खबर।

✦ कौशल शर्मा, अस्सरघाट, बनारस, यूपी

पर्यटन विभाग

मिश्रा जी,

मैं केवल सच पत्रिका का नियमित पाठक हूँ और इसके सभी अंकों का संपादकीय एवं शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की खबरों को पूरे मन से पढ़ता हूँ। बिना डरे भ्रष्टाचारियों को बेनाकाब करने का कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं। जून 2025 अंक में “अवैध संविदा अधिकारी चला रहे हैं पर्यटन विभाग” भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का पर्दाफास करने में खबर कामयाब होती दिख रही है। पूरे प्रमाण के साथ खबर लिखने की शैली की वजह से अधिकारी भी परेशान रहते हैं की आखिरकार दस्तावेज कौन उपलब्ध कराता है। धारदार एवं दमदार खबर के लिए बधाई।

✦ कैलाश पाठक, जी बी रोड, गया, बिहार

झारखंड की खबरे

संपादक जी,

झारखंड प्रदेश की पुलिस की खबरों के साथ-साथ राजनीति की खबरों को भी पूरी प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया जाने लगा है। गुड्डी साव की राजनीतिक खबरें जानकारीप्रद है और सकारात्मक बिन्दुओं को महत्व देता है तो पुलिस के द्वारा किये जा रहे कार्यों का बहुत महत्व दिया जाता है लेकिन पुलिस कहां-कहां भ्रष्टाचार कर रही है उसपर कोई भी खबर नहीं आ रहा है। विभाग में फैले भ्रष्टाचार की खबरों को भी प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया जाये। कई खबरें कई राज्यों की है जो काफी पठनीय है तथा चुनाव के लिए उपयुक्त है।

✦ अभिषेक राय, 104, हाउसिंग कॉलोनी, राँची

शून्य से शिखर

ब्रजेश जी,

जून 2025 अंक का संपादकीय वास्तव में मंथन करने योग्य है। “शून्य से शिखर” शीर्षक ही सबकुछ बयां कर देता है। आपका संपादकीय सच में आईना का काम करता है क्योंकि आप किसी भी समस्या के तह में जाकर उसके समाधान का मार्ग को भी बताने की सार्थक प्रयास रहता है। विभिन्न मुद्दे को प्राथमिकता के साथ बिना लाग लपेट के निष्कर्ष के साथ आपकी लेखनी ही आपकी मजबूत पहचान है। आपका जून अंक का संपादकीय सटीक एवं उपयोगी है। ऐसे ही विषयों पर कलम चलती रहनी चाहिए।

✦ प्रभुदयाल सक्सेना, गाँधी नगर, नई दिल्ली

आर्यभट्ट

मिश्रा जी,

“शून्य से खिर तक” विशेषांक में पत्रकार अमित कुमार की खबर सही मायने में भारत की ऐतिहासिक गौरवशाली क्षणों की अनुभूति कराता है। जून 2025 अंक में गणितज्ञ आर्यभट्ट के योगदान पर पूर्ण विस्तार से हर पहलुओं को ध्यान केंद्रित करके लिखा गया है जिससे वर्तमान युवा पीढ़ी को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लाभ मिलेगा। आर्यभट्ट के खगोलीय विश्लेषण को भी प्राथमिकता के साथ स्थान दिया गया है। यह अंक काफी सराहनीय होने के साथ-साथ सूचना देने का मजबूत केंद्र दिख रहा है। इसके कई खबरें समाज की आंख खोलती नजर आ रही है। इस प्रकार का विशेषांक काफी जानकारी देता है।

✦ कौशलेन्द्र सिंह, टावर चौक मुंगेर, बिहार

शुभकामनाएं

संपादक जी,

जून 2025 अंक काफी अधिक पृष्ठों वाला था जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सहित बिहार के सांसद, मंत्री का शुभकामनाएं पढ़कर अच्छा लगा। आर्यभट्ट जैसे विद्वान के उपर विशेषांक सच में पठनीय एवं संग्रहनीय है। शून्य के एक-एक योगदान को बहुत ही बारीकी के साथ पाठकों के समक्ष रखा गया है जिससे युवा पीढ़ी को सर्वाधिक लाभ होगा और प्रेरणा मिलेगी की राष्ट्रहित में किये गये कार्य की चर्चा ही काल खंड में होती रहेगी। केवल सच, पत्रिका निरंतर उत्कृष्ट कार्य को संपादित कर लोगों का विश्वास जीतता जा रहा है।

✦ आशुतोष वर्णवाल, कचहरी रोड, मुजफ्फरपुर

अन्दर के पन्नों में

31



37



शरबत विक्रेता हत्याकाण्ड.....53

नवादा विधानसभा में चढ़ा सियासी तापमान
2025 में चुनावी मुकाबला
दिलचस्प होने के आसार



61

RNI No.- BIHHIN/2006/18181,

DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत

खुशहाल भारत



केवल सच

निर्भीकता हमारी पहचान

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका



वर्ष:- 20

अंक:- 230

माह:- जुलाई 2025

मूल्य:- 20/- रु

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र

श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769

8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका (एडमिन) 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

रामानंद राय 9905250798

डॉ० शशि कुमार 9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

प्रसन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

पंकज कुमार सिंह 9693850669, 9430605967

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय 7992210078

संतोष कुमार यादव 8210487516

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

अविनाश कुमार 7992258137, 9430985773

कुमार अनिकेत 9431914317

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

ऋषिकेश पाण्डेय 7488141563, 7323850870

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०):-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०):-	गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०):-	मुकेश कुमार	9473038020
बाढ़ :-		
भोजपुर :-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर :-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर :-		
रोहतास :-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
:-		
गया (श०):-	सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०):-		
औरंगाबाद :-		
जहानाबाद :-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल :-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा :-		
:-		
नवादा :-	अमित कुमार	9162664468
:-		
मुंगेर :-		
लखीसराय :-		
शेखपुरा :-		
बेगूसराय :-		
:-		
खगड़िया :-		
समस्तीपुर :-		
जमुई :-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली :-		
:-		
छपरा :-		
सिवान :-		
:-		
गोपालगंज :-		
:-		
मुजफ्फरपुर :-		
:-		
सीतामढ़ी :-		
शिवहर :-		
बेतिया :-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा :-		
मोतिहारी :-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा :-		
:-		
मधुबनी :-		
:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा :-		
मधेपुरा :-		
सुपौल :-		
किशनगंज :-		
:-		
अररिया :-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया :-		
कटिहार :-		
भागलपुर, :-		
(ग्रा०):-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया :-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., **स्टेट हेड**

सम्पर्क करें
9308815605

प्रधान संपादक**झारखण्ड स्टेट ब्यूरो****झारखण्ड सहायक संपादक**

अभिजीत दीप 7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र 7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव 9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023

संयुक्त संपादक**विशेष प्रतिनिधि**

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
:- ओम प्रकाश 9708005900

साहेबगंज :-
खूंटी :-
जमशेदपुर :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता 9304824724
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंकलेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., **स्टेट हेड**
सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768

BANK :- Punjab National Bank

IFSC Code :- PUNB0060020

PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 0600050004768

BANK :- State Bank of India

IFSC Code :- SBIN0003564

PAN No. :- AAJFK0065A



श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

‘केवल सच’ पत्रिका एवं ‘केवल सच टाइम्स’

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654



डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

‘केवल सच’ पत्रिका

एवं ‘केवल सच टाइम्स’

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251



सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक “मगध इंटरनेशनल स्कूल” टेकारी

“ केवल सच ” पत्रिका एवं “ केवल सच टाइम्स ”

9060148110

sudhir4s14@gmail.com



कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

‘केवल सच’ पत्रिका एवं ‘केवल सच टाइम्स’

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	धर्मेन्द्र सिंह	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

महेश चौधरी	9572600789, 9939419319
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सूमन सौरभ	9471492480, 7004952447
शालनी झा	9031374771, 7992437667
बंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
कुमार राजू	9310173983
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो

राँची	गुड्डा साव	6299470142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाईबासा		



मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष क्यों कर रहा बवाल?

महागठबंधन के विरोध मार्च में कन्हैया-पप्पू का अपमान!

‘सूत्र’ को ‘मूत्र’ समझते हैं तेजस्वी

● अमित कुमार

ठां

य....ठांय की गूंज से राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में हत्याओं का दौर पुराने जंगल राज पर हावी

होता दिख रहा है। एक तरफ सीएम नीतीश अपनी मानसिक संतुलन का परिचय हर दिन दिखा रहे हैं और सहयोगी भाजपा मौन व असमंजस में क्या करे, क्या ना करे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। उनके साथ सरकार चलाने की

मजबूरी भी है, इसलिए नीतीश भी जरूरी हैं। दिगर बात है कि गृह विभाग को स्वयं संभाले नीतीश पुलिस को अपराध रोकने की हिदायत तो देते हैं किन्तु इस पर अमल करने में बिहार के पुलिस प्रशासन अक्षम दिख रहे हैं। पुलिस महकमे

में शीर्ष पदों पर पुलिस विभाग के सूरमाओं की अंबार है किंतु अपराधियों के आगे वह भी घुटने टेक दिये हैं। किसी एक अपराध को अपराधी कारित करते हैं तो पुलिस तुरंत उसके अनुसंधान में जुट जाती है पर अनुसंधान पूरा होने के पहले कई अपराधिक वारदात पुनः हो जाते हैं। इसे पुलिस प्रशासन की विफलता कहे या अपराधियों के बढ़ते बुलंद हौसले। अब तो सरेआम, खुलेआम हत्यारे हथियार लहरा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ऐसा देखने को मिल रहा है, मानों अपराधियों में पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है। हाल के दिनों की घटनाएं, जिनमें देखा गया कि अपराधी कार से उतरकर बाइक मैकेनिक को गोली मार कर हथियार लहराते निकल जा रहे हैं तो वही नामी अस्पताल पारस में, जहां सिक्योरिटी टाइट होने के बाद भी एक नहीं पांच-पांच अपराधी अत्याधुनिक हथियार के साथ हत्या को अंजाम देकर निकल जा रहे हैं। हां ऐसा नहीं है कि अपराधी पकड़े नहीं जा रहे किन्तु अपराधियों में पुलिस का डर समाप्त हो चुका है, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस ने एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन के नेतृत्व में 72 घंटे में मुख्य आरोपी उमेश को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के लिए उनकी



विनय कुमार
डीजीपी बिहार

जमकर सराहना हुई थी। लेकिन अब किसानों के लेकर दिए गए बयान ने उनकी भद्दा पिटवा दी। एडीजी कुंदन कृष्णन द्वारा कहा जाना कि “ज्यादातर हत्याएं अप्रैल, मई और जून के महीने में होती हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक बारिश नहीं आ जाती, क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास काम नहीं होता और इसी दौरान अपराध बढ़ते हैं।” यह बयान बेतुका और मजाकिया बनकर सरकार की फजीहत करा रही है। सरकार एक तरफ सड़क और पुलों के निर्माण और उद्घाटन के साथ सरकारी

नौकरियां देने तथा बिजली मुफ्त देने जैसे विकास के कार्य कर रही है। वह चुनाव में जनता के बीच इसे भंजाना चाहती है किन्तु घटित वारदातों पर पुलिस का ऐसा बेतुका बयान आना गृह विभाग संभाले सीएम नीतीश कुमार के लिए शर्मसार है। अभी सीएम नीतीश दीमागी तौरपर स्वस्थ नहीं दिख रहे, उनकी हरकते आये दिन मीडिया की सुर्खिया बटोरती है तो दूसरी तरफ पुलिस द्वारा हत्याओं के लिए किसानों मजदूरों को जिम्मेदार ठहराकर पुलिस प्रशासन सरकार के वोटों को गिराने का काम कर रही है। एडीजी के बयान के बाद सभी दल के नेताओं ने जमकर निशाना साधा था। हालांकि इस बढ़ते विवाद के बीच एडीजी ने माफी मांग ली है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा, “सभी किसान भाई को नमस्कार। पिछले दिनों आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मेरे द्वारा कहे गए कुछ शब्दों को तोड़-मरोड़ के पेश किया गया। इससे एक विवाद खड़ा हुआ है। मेरे द्वारा जो कहा गया उसका तात्पर्य यह नहीं था कि मेरे देश के किसान भाई और हमारे अन्नदाता का किसी भी आपराधिक घटनाओं से लेना-देना है। वो मेरे लिए हमेशा सम्मान के पात्र हैं। मेरे पूर्वज भी किसान थे। मैं भी किसान समाज से गहरा संबंध रखता हूं। हर आपराधिक घटनाओं के पीछे अपराधी होता है। कोई जाति या धर्म



चंदन मिश्रा

उमेश यादव

गोपाल खेमका

कुंदन कृष्णन



विशेष नहीं होता है। मेरे मन में किसान के प्रति काफी आदर है। लेकिन फिर भी अगर मेरे वक्तव्य के द्वारा किसी के मन को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ।”

बहरहाल, एक के बाद एक सिलसिलेवार हत्याओं के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक मंच पर नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। सत्ता की लोलुपता को मन में पाले अपने दिये बयान के शब्दों में निर्लजता को दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वही सुर्खियों में बने रहने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर पलटवार करते दिख रहे हैं। बिहार की एनडीए सरकार एक तरफ विकास गाथा को जनता के बीच प्रमोट करने में जुटी है तो दूसरी ओर महागठबंधन, खासकर आरजेडी और कांग्रेस ने हालिया बिहार में घट रही एक के बाद एक जघन्य अपराधिक घटनाओं को लेकर जनता में डबल इंजन की सरकार को खूनी सरकार चलाने का डंका पीट रही है। जब एनडीए और महागठबंधन के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है, ऐसे में प्रशांत किशोर की जनसुराज

पीछे कैसे रह सकती है। पीके का सरकार पर आरोप लगाना की “विकास अगर है तो बिहार से बेरोजगारों का पलायन क्यों” और आरजेडी तथा कांग्रेस पर प्रहार करते हुए यह जाहिर करना की पुराने जंगल राज की पोषित पार्टी का अपराध पर बयान देना बेतुकी बात है, को जनता के बीच समझा रहे हैं। चुनावी समर के बीच आगे



निकलने की रेस में शब्दों में निर्लजता दिखायी जा रही है, जिसे आम जनता कतई पसंद नहीं करना चाहेगी। बता दें कि बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर आयोजित

महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दे दिया। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी मिली है कि बिहार की वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के नाम हैं जिनमें नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के सिटीजन शामिल हैं। जिसके जवाब में तेजस्वी ने चुनाव आयोग के सूत्र को ‘मूत्र’ बता डाला। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बवाल मच गया। किसी भी निष्पक्ष बात को रखने के लिए सूत्रों का हवाला दिया जाता है, खासकर मीडिया जगत में सूत्र ही वह माध्यम होते हैं, जिनसे जानकारी इकट्ठा की जाती है जो पूरी तरह से गोपनीय होती है और मीडिया उसे सूत्र बताती है। अब ये तो राजद नेता तेजस्वी की मानसिकता निर्जलतापूर्ण है कि मीडिया के सूत्र को सरेआम अपमानित करते हुए उसे वह ‘मूत्र’ कह रहे हैं। ज्ञात हो कि यही वह सूत्र जिन्हें वह ‘मूत्र’ से संबोधित कर रहे हैं, राजनीति करने में अहम किरदार निभाते आये हैं। यही मीडिया के





सूत्र ने उन्हें उनकी अलग पहचान दिलायी है। उनके चुनावी जीत-हार का कारण भी यह सूत्र ही बताते हैं, जिनके बदौलत वह राजनीति कर रहे हैं। विडम्बना है कि वही सूत्र उनके लिए 'मूत्र' है। यह 'सूत्र और 'मूत्र' का विवाद क्यों उत्पन्न हुआ तो बता दें कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस वार्ता बुलायी थी। मीडिया पर खीर खाये तेजस्वी की निर्लजतापूर्ण बयान शर्मनाक है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के इस दावे पर सवाल उठाया कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तेज गति से चल रहा है और 25 जुलाई की समय सीमा से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उच्चतम न्यायालय के इस सुझाव पर निर्वाचन आयोग की 'चुप्पी' पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि आधार कार्ड और

राशन कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इन दस्तावेजों को उन मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना है जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, जब आखिरी बार एसआईआर कराई गई थी। तेजस्वी ने कहा, "निर्वाचन आयोग ने जारी अपने प्रेस नोट



में दावा किया है कि राज्य के 7.90 करोड़ मतदाताओं में से 80 प्रतिशत से अधिक मतदाता पहले ही एसआईआर के तहत गणना फार्म जमा करा चुके हैं। यह एक हैरान करने वाला दावा है, क्योंकि अनुमानतः

बिहार के चार करोड़ लोग अन्य राज्यों में रहते हैं।" पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम निर्वाचन आयोग से जानना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया में कितने प्रवासियों को शामिल किया गया है। यह सर्वविदित है कि चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए अपने गृह राज्य लौटते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, अनुमानित 40 लाख प्रवासियों के लिए कई विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन करना पड़ा। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि इस बार क्या व्यवस्था की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग आंकड़ों के साथ खेल रहा है ताकि यह गलत धारणा बने कि वह यह काम

कुशलतापूर्वक कर रहा है। तेजस्वी ने कहा कि हमें शिकायतें मिली हैं कि बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) लक्ष्य हासिल करने के लिए दबाव में हैं और वे संबंधित मतदाताओं से विधिवत हस्ताक्षर और भराई करवाए बिना ही गणना प्रपत्र एकत्र कर रहे हैं। राजद नेता ने कुछ वीडियो क्लिप भी चलवाए, जिनमें गणना प्रपत्र सड़कों पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इसे यह बताने के लिए दिखाया कि प्रक्रिया में कई अनियमितताएं हैं। हालांकि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 'एक्स' हैंडल पर इन वीडियो को खारिज करते हुए 'फैक्ट चेक' चला रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया, "निर्वाचन आयोग कभी भी उचित बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह नहीं बताता कि वह इस सप्ताह के शुरू में दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश के बारे में क्या करना चाहता है, जिसमें उसे आधार कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करने पर विचार करने को कहा गया था।" उन्होंने कहा कि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि राजनीतिक दलों द्वारा नामित बूथ स्तरीय





एजेंटों को इस प्रक्रिया में क्या भूमिका निभानी है। तेजस्वी ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने 25 जुलाई की समय सीमा को पूरा करने की जल्दबाजी में एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो लोग अपने दस्तावेज जमा नहीं कर सकते, वे अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं, तथा शेष चीजें दावे/आपत्तियों के चरण के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं दी गई, और बीएलओ असमंजस में हैं।” तेजस्वी को इस वर्ष के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए विपक्षी ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंकलूसिव अलायंस’ (इंडिया गठबंधन) की समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तेजस्वी ने गठबंधन के कई सहयोगियों की मौजूदगी में कहा, “हमारा अब भी मानना है कि एसआईआर एक ऐसी कवायद है जिसका उद्देश्य सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को फायदा पहुंचाने के लिए, कई मौजूदा मतदाताओं को उनके मताधिकार से गलत तरीके से वंचित करना है। इस अलोकतांत्रिक कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेताओं को सीधे तौर पर दोषी ठहराया जाना चाहिए।” उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनावों में कई सीटें ऐसी थीं जिन पर महागठबंधन (बिहार के लिए विपक्षी गठबंधन का नाम) के उम्मीदवार 3,000 या उससे कम वोटों के अंतर से हार गए थे। तेजस्वी ने कहा कि मतदाता सूची में थोड़ी सी भी हेराफेरी आसानी से पलड़ा पलट सकती है, अगर निर्वाचन आयोग को वाकई लगता है कि मतदाता सूची अब तक संदिग्ध रही है, तो उसे पिछले साल के लोकसभा चुनावों को रद्द घोषित कर देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा

के इस दावे का मखौल उड़ाया कि मतदाता सूची से ‘अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्याओं’ को बाहर निकालने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। पिछले साल भी राजग ने राज्य की 40 में से 30 सीटें जीती थीं। इसलिए भाजपा को हमें बताना चाहिए कि क्या उसे लगता है कि कथित घुसपैठिए नरेन्द्र मोदी को वोट दे रहे थे।

वही इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए धांधली की गई। केंद्र की राजग सरकार इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनावों में भी ऐसा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ पटना में निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक विरोध

मार्च के दौरान ‘इंडिया’ गठबंधन के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची में हेराफेरी करने के ‘महाराष्ट्र मॉडल’ का विस्तार है और इससे न केवल लोगों के वोट देने के अधिकार को बल्कि उनके पूरे भविष्य को हथिया लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को संविधान की रक्षा करनी चाहिए। वह भाजपा के निर्देशों पर काम कर रहा है। इन निर्वाचन आयुक्तों को भाजपा ने ही नामित किया है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चुनावी चोरी का एक प्रयास है। हम निर्वाचन आयोग को मतदाताओं, खासकर युवाओं के अधिकार छीनने नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग में भाजपा द्वारा नामित लोग शामिल हैं और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य सत्तारूढ़ पार्टी की सेवा करना है। ज्ञात हो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राजधानी पटना पहुंचे। उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, भाकपा महासचिव डी राजा और अन्य विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता भी थे। गांधी राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहां आए। यह प्रदर्शन चार नई श्रम संहिताओं के खिलाफ श्रमिक संगठनों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी ‘चक्का जाम’ का हिस्सा है। देशव्यापी हड़ताल के तहत बिहार में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुद्दा भी जोड़ा गया है। संविधान की लाल प्रति दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा-आरएसएस की भाषा बोल रहा है। पहले निर्वाचन आयोग के सदस्यों के चयन में भारत के प्रधान न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल





होते थे लेकिन अब हमें इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है और भाजपा द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्तों के नामों वाला एक कागज थमा दिया गया। गांधी ने महाराष्ट्र की मतदाता सूची में कथित तौर पर फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम महाराष्ट्र मॉडल का पहले ही पर्दाफाश कर चुके हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में भाजपा नीत गठबंधन ने पिछले साल विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की थी, जबकि कुछ महीने पहले ही लोकसभा चुनावों में उसका निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में महागठबंधन द्वारा आहूत राज्यव्यापी बंद के मद्देनजर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के सड़कों पर उतरने से राज्य के कई हिस्सों में रेल और सड़क यातायात

बाधित हो गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में अपराध की कई हालिया घटनाओं को लेकर आरोप लगाया कि यह प्रदेश क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री 'कमीशन' कमा रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बार सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि बिहार में 11 दिनों में 31 हत्याएं हुई हैं। उन्होंने एक खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि बिहार में 11 दिनों में 31 हत्याएं हुई हैं। कांग्रेस नेता ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, बिहार बना 'क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया'— हर गली में डर, हर घर में बेचैनी। बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है गुंडाराज। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री कुर्सी बचा रहे हैं,

भाजपा के मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। वहीं राहुल गांधी के बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है वाले बयान का समर्थन करते हुए तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने एकदम सही कहा है कि बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है। राज्य में हर दिन लोगों की हत्या हो रही है। हर दिन अपहरण और रेप की घटनाएं हो रही हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सभी लोग अचेत अवस्था में चले गए हैं।

बताते चले कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का बवाल चल ही रहा था, इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान में कहा कि बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कुमार की यह घोषणा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि अगले पांच साल में (2025 से 2030) वर्ष 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है तथा 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी/रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सात निश्चय' कार्यक्रम के तहत राज्य



नीतीश का चुनावी ऑफर

01 125 यूनिट तक फ्री बिजली

02 वृद्धा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100

03 विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100

04 सरकारी भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू

05 अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी का वादा



के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुमार ने कहा कि अगले पांच वर्षों में युवाओं के कौशल विकास के लिए 'सात निश्चय' के तहत जारी कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। आने वाले समय में कौशल विकास के लिए एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम बिहार के गौरव भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा ताकि राज्य के युवाओं को कौशल विकास की नई दिशा मिल सके। उन्होंने कहा कि 2005 से 2020 के बीच बिहार के आठ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी तथा रोजगार उपलब्ध कराने की गति को और तेज करने के लिए, 2020 में सुशासन के कार्यक्रम 'सात निश्चय-2' के तहत हमने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया था। बाद में, इस लक्ष्य को बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य कर दिया गया। अब बिहार कैबिनेट ने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए अगले पांच सालों में एक करोड़ नई नौकरी और रोजगार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रम संसाधन विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद तेजस्वी यादव का रिएक्शन आया है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दरअसल, बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए अगले पांच साल में एक करोड़ नौकरी

और रोजगार देने की घोषणा की थी। अब सरकार के उस घोषणा पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। अगले पांच वर्षों में सरकार राज्य के एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करेगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने आजतक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इन लोगों को कुछ भी कहना है तो कहने दीजिए, ये तो नकलची सरकार है। नीतीश कुमार के मुंह से आजतक किसी ने सुना है यह बात, सामने



आकर उनको कहना चाहिए। चुनाव आने वाला है और ये लोग जाने वाले हैं, विदाई तय है तो जो बोलना है बोल लें। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि आप लोग तो पूछिएगा नहीं कि एक करोड़ नौकरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बता दें कि तेजस्वी के लाख आरोपों और प्रश्नों को किनारे रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नये-नये घोषणाओं से बिहार की जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। वही नौकरी देने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था की नीतीश कुमार ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आम जनता को राहत देते हुए 125

यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है।

यह फैसला 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और जुलाई माह के बिल से ही इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस निर्णय की

जानकारी ट्वीट के माध्यम से

साझा की। उन्होंने कहा, "हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब तय कर लिया गया है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।" नीतीश सरकार के इस फैसले से राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। यह योजना खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों



Nitish Kumar
@NitishKumar

Translate post

हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा।

कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी।

8:00 AM · Jul 17, 2025 · 80.6K Views



के लिए बड़ी राहत साबित होगी। नीतीश कुमार ने कहा, 'हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125

यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि इन प्रयासों से न केवल बिजली का खर्च घटेगा, बल्कि अगले तीन वर्षों में राज्य को लगभग 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी, जिससे बिजली संकट भी काफी हद तक खत्म होगा। दिगर बात है कि सीएम नीतीश के इस घोषणा के बाद से बिहार की जनता के बीच खुशी का माहौल है। यहां सवाल यह भी है कि क्या ये सिर्फ चुनावी घोषणा है या चुनाव के बाद भी

यह जारी रहेगा? 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ चुनाव के जीत हार पर असर नहीं डालेगा! वही तेजस्वी यादव भले ही सीएम नीतीश और एनडीए का मखौल बनाये किन्तु फिलवक्त तो सीएम नीतीश नये-नये घोषणाओं से तेजस्वी पर भारी पड़ रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी की माई-बाप योजना का लाभ बिहार की जनता कब उठायेगी, ये तो भविष्य बतायेगा। किन्तु 1 अगस्त 2025 से सीएम के 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ

बिहार की जनता लेने जा रही है, ऐसी घोषणा की गई है। वही दूसरी तरफ सीएम नीतीश की लोक लुभावन घोषणा पर बढ़ते अपराध पानी फेर रहे हैं। विपक्ष ने तो इसे महा जंगलराज का नाम दे दिया है। बिहार समेत राजधानी पटना रक्तरंजित और खून से पटी दिखने लगी है। बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के बाद राजधानी पटना के पारस अस्पताल में अत्याधुनिक हथियार से लैश पांच अपराधियों द्वारा इलाजरत चंदन मिश्रा की हत्या कर देना पुलिस प्रशासन के कार्यों पर सवाल खड़ा कर



रही है। चंदन मिश्रा हत्या मामले में आई.जी. पटना जितेन्द्र राणा द्वारा कहा गया कि चंदन मिश्रा का अपराधिक इतिहास है और हत्या के मुकदमे भी चल रहे हैं और पेरोल पर चंदन जेल से बाहर था और अपने इलाज के लिए पारस में भर्ती था। पारस अस्पताल की इस घटना से लॉ एण्ड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे हैं, जिसकी नुकसान की भरपाई शायद नीतीश कुमार को चुनाव में उठानी पड़ सकती है!

गौरतलब है कि बिहार की सियासी जमीन इन दिनों फिर से चर्चा में है। अपराधिक वारदातों के बीच निवार्चन आयोग द्वारा करायी जा रही मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में 9 जुलाई को पटना में महागठबंधन की ओर से आयोजित बिहार बंद प्रदर्शन में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसपर खूब बातें हो रही है। NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को राहुल गांधी की प्रचार वैन पर चढ़ने से सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। ये सब उस वक्त हुआ जब राहुल

गांधी और तेजस्वी यादव मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे और भीड़ जोश में उमड़ रही थी। बिहार बंद के इस आयोजन में जैसे ही कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, राहुल गांधी की प्रचार वैन पर चढ़ने लगे, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पप्पू यादव भीड़ में घिरे हुए हैं और वैन पर चढ़ते वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़े। घटना के बाद पप्पू यादव ने बताया कि उन्हें पैर में चोट लगी है, लेकिन इसे अपमान कहना गलत होगा। उन्होंने कहा,

“मैं गिर गया, मुझे चोट लगी। लेकिन यह अपमान नहीं है। कौन इसे कैसे देखता है, वो उस पर है। जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर उनके लिए लाख बार भी अपमान सहना पड़े, तो मंजूर है।” हालांकि बिहार बंद के दिन जो नजारा सामने आया, वो महज सिक्योरिटी की चूक नहीं लग रहा। चर्चा ये है कि क्या राहुल गांधी की वैन से कन्हैया और पप्पू यादव को दूर रखना सिर्फ सुरक्षा की वजह थी या फिर इसके पीछे



राहुल गांधी एवं मल्लिकार्जुन खरगे



पप्पू यादव

कोई और वजह थी। तेजस्वी यादव पर उंगलियां उठ रही हैं। याद दिला दें, तेजस्वी यादव को लेकर कई बार ये देखा गया है कि वो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से मंच साझा करने से कतराते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इन दोनों नेताओं को किनारे किया गया हो। पुराने कई कार्यक्रमों में भी तेजस्वी ने इन दोनों से दूरी बनाए रखी है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने खुलकर विरोध किया। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस ने पप्पू को टिकट नहीं दिया और आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतार दिया, जो बुरी तरह हार गई। अब पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन उनकी नजदीकियां अब भी कांग्रेस से बनी हुई हैं। बिहार बंद के दिन भी वो कांग्रेस का झंडा थामे दिखे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी पर जब भी कोई संकट आया तो पप्पू यादव चट्टान की तरह उनके साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन बदले में उन्हें हमेशा अपमानित ही किया गया। बिहार बंद को सफल बनाने के लिए पप्पू यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वे सुबह से ही सड़क पर डटे हुए थे। पूर्णिया से लेकर पटना तक उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर कई जगहों पर रेल तक रोक दी। इस कारण से कई लोगों पर मुकदमा तक दर्ज हो गया है। इससे अब वह समर्थक कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए। इतना सबकुछ करने के बाद भी पप्पू यादव को अपमानित ही होना पड़ा। उन्हें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ट्रक पर चढ़ने तक नहीं दिया गया। पप्पू यादव के साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को सुरक्षाकर्मियों ने ट्रक पर चढ़ने से रोक दिया। यह घटनाक्रम पटना में आयकर गोलंबर के पास देखने को मिला। अब एनडीए नेता इस घटना पर मजे ले रहे हैं तो पप्पू यादव

के समर्थक इसे अपने नेता का अपमान बता रहे हैं। पप्पू यादव के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। राजद अध्यक्ष लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कारण उन्हें पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा था। पप्पू को हराने के लिए तेजस्वी ने एनडीए प्रत्याशी को वोट करने की अपील कर डाली थी और कांग्रेस पार्टी ने मुंह तक नहीं खोला था। इसके बाद भी राहुल गांधी जब-जब बिहार आए तो पप्पू यादव ने उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन लालू परिवार के कारण ऐसा हो नहीं सका। बिहार बंद के दौरान जो कुछ हुआ पप्पू यादव ने उसका भी बुरा नहीं माना है। एक निजी चैनल ने जब पप्पू यादव से

साफ है कि बिहार में जबतक पप्पू यादव जैसे कांग्रेसी हैं, पार्टी का झंडा बुलंद रहेगा।

विडम्बना है कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लोकसभा चुनाव से पहले ही अपनी 10 साल पुरानी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है। पप्पू यादव यहां तक कहते हैं कि मेरी शवयात्रा कांग्रेस के ही झंडे में ही निकलेगी। ऐसे में राहुल गांधी जब बिहार बंद के दौरान पटना आए तो पप्पू यादव क्यों पटना एयरपोर्ट पहुंचे? वे पटना एयरपोर्ट से तीन किलोमीटर दूर हाथ में कांग्रेस का झंडा लेकर क्यों सचिवालय हॉल पर ट्रेन रोकते नजर आए? साफ है कि कांग्रेस उनके लिए मजबूरी है, कांग्रेस के लिए पप्पू कोई जरूरी नहीं हैं। पप्पू यादव बार-बार अपने को कांग्रेस का नेता बताते हैं। लेकिन कांग्रेसी पप्पू यादव को कभी भी कांग्रेसी नहीं मानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव कांग्रेस के एक सीनियर नेता और राज्यसभा सदस्य से मिलने गए थे। पप्पू यादव ने उसने कांग्रेस से टिकट देने का जब आग्रह किया तो कांग्रेस के सीनियर नेता ने हंसते हुए तपाक से कहा था कि यादवों की पार्टी तो आरजेडी है, फिर कांग्रेस से क्यों टिकट मांग रहे हैं? इससे साफ कांग्रेसी पप्पू यादव को अभी तक अपने परिवार का सदस्य नहीं मान रहे हैं तो फिर पप्पू यादव की ऐसी क्या मजबूरी है कि पप्पू यादव अपमान का घूंट पीकर भी कांग्रेस के साथ ही खड़ा रहना चाहते हैं। पप्पू यादव के सामने वर्तमान समय में कोई विकल्प नहीं है। पप्पू यादव बीजेपी में जा नहीं सकते। आरजेडी से उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं। पप्पू यादव के लालू यादव के साथ ही रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पप्पू यादव से आरजेडी तेजस्वी को खतरा मानती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से उनकी बन नहीं रही है। क्योंकि जन सुराज पार्टी ने पूर्णिया से बीजेपी के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह



इस अपमान पर

सवाल किया तो पूर्णिया सांसद ने कहा कि ये मेरे लिए कोई अपमान-सम्मान की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं था, इसलिए भी मुझे चढ़ने नहीं दिया गया होगा। हम गरीबों के दिल में रहते हैं। देश हमको हीरो मानता है। पार्टी के प्रति निष्ठा को लेकर पप्पू यादव के इस बयान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उनके इस बयान से एक बात तो



तारिक अनवर



राजेश कुमार



कन्हैया

को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। यही कारण है कि पप्पू यादव के लिए कांग्रेस पप्पू यादव के लिए मजबूरी है।

बहरहाल, निर्दलीय लोकसभा सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित एक बैठक में शामिल हुए और कहा कि पार्टी उन्हें राज्य विधानसभा चुनाव में जो भूमिका देगी उसे निभाएंगे। बता दें कि पटना में विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ मार्च के दौरान कन्हैया कुमार के साथ पप्पू यादव को महागठबंधन के नेताओं वाले ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया था। उस ट्रक पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवार थे। इस घटनाक्रम के बाद यादव की राहुल गांधी से पहली बार मुलाकात हुई है। सूत्रों का कहना है कि यादव के खरगे और राहुल के साथ अलग से भी मंथन किया। बैठक के दौरान पप्पू यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में एक सवाल के जवाब में

यह भी कहा कि बिहार में कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के चेहरों की कोई कमी नहीं है। यादव ने मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस के चेहरों का उल्लेख करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और सांसद तारिक अनवर के नामों का उल्लेख भी किया। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और कई अन्य शामिल थे। कांग्रेस मुख्यालय में बिहार चुनाव को लेकर हुई किसी बैठक में पप्पू यादव पहली बार शामिल हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि पार्टी उन्हें राज्य विधानसभा चुनाव में जो भूमिका देगी उसे निभाएंगे। यादव ने मुख्यमंत्री

पद के कांग्रेस के चेहरों का उल्लेख करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और सांसद तारिक अनवर के नामों का उल्लेख भी किया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि बिहार में कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के चेहरों की कोई कमी नहीं है। यादव ने मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस के चेहरों का उल्लेख करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और सांसद तारिक अनवर के नामों का उल्लेख भी किया। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और कई अन्य शामिल थे। कांग्रेस मुख्यालय में बिहार चुनाव को लेकर हुई किसी

को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर रखा है। यह पहली बार था जब पप्पू यादव कांग्रेस की किसी बिहार चुनाव संबंधी रणनीतिक बैठक में शामिल हुए। बैठक में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद थे। चर्चा आगामी चुनाव में गठबंधन की रणनीति को लेकर हुई। सूत्रों के मुताबिक, पप्पू यादव की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से अलग से भी बातचीत हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कई योग्य चेहरे हैं। राजेश राम और तारिक

अनवर इनमें से हैं। मैं राहुल गांधी की विचारधारा को बिहार के हर घर तक ले जाने की कोशिश करूंगा। पप्पू यादव के इस बयान से नाराज राजद ने कहा है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, हैं और रहेंगे। पप्पू यादव जो कह रहे हैं, वह कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है।

2020 में भी तेजस्वी चेहरा

थे, 2025 में भी वही होंगे। इस मुद्दे पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की राय ही मायने रखती है।

वही दूसरी ओर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में 'महागठबंधन' की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव के प्रमुख चेहरा होने को लेकर कोई असमंजस और विवाद नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के जीतने पर सबसे बड़े घटक दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का नेता ही स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि चुनाव में मुद्दे



बैठक में पप्पू यादव पहली बार शामिल हुए हैं। बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। इस बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस के पास भी कई मुख्यमंत्री पद के योग्य चेहरे हैं, जिनमें उन्होंने राजेश राम और तारिक अनवर का नाम लिया। इस बयान के बाद महागठबंधन के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खासकर राजद खेमे में बेचैनी देखी जा रही है, जिसने पहले ही तेजस्वी यादव



कन्हैया कुमार

महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक 'साजिश' के तहत इनसे ध्यान भटकाने के लिए बार-बार चेहरे की बात की जा रही है। कुमार का यह भी कहना था कि अगर पार्टी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो वह जरूर लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। बिहार में 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन के घटक दलों के गठजोड़ को 'महागठबंधन' के नाम से जाना जाता है। इस गठबंधन में वाम दलों के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल हैं। वही बिहार में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के बारे में पूछे जाने पर कन्हैया कुमार ने कहा कि मेरे खयाल से पिछली बार भी बदलाव का माहौल था। थोड़े अंतर से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। पिछले पांच वर्षों से बिहार की जो स्थिति है, उससे लगता है कि इस बार बदलाव की बयार पहले से ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के प्रभारी ने महागठबंधन के घटक दलों का उल्लेख करते हुए कहा कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जिसकी बड़ी जिम्मेदारी है वह निभाएगा और जिसकी छोटी जिम्मेदारी है, उसका भी निर्वहन जरूरी है। एक चुटकी नमक कम तो खाना बेस्वाद और एक चुटकी ज्यादा हो तो भी खाना बेस्वाद... इसलिए सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। बिहार में कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में शुमार नेता कन्हैया कुमार ने महागठबंधन में सीनियर और जूनियर घटक के विचार को खारिज करते हुए कहा कि सभी दलों की अपनी भूमिका है और वे एकजुट होकर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यदि

आप गाड़ी को देखें तो उसमें क्लच उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितना ब्रेक और रियर व्यू मिरर भी महत्वपूर्ण होते हैं। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे और तेजस्वी यादव से जुड़े सवाल पर कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह जनता तय करती है। जिसके पास संख्याबल है वह मुख्यमंत्री बनेगा। स्वाभाविक रूप से राजद ज्यादा सीटों पर लड़ेगा और ज्यादा सीटों पर जीतेगा। संख्याबल उसके पास होगा और मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी होगी, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। यह पूछा गया कि क्या प्रमुख चेहरा तेजस्वी का है और इसको लेकर महागठबंधन में कोई असमंजस नहीं है? इस पर कन्हैया ने कहा कि इसमें कोई संदेह, संकट या विवाद नहीं है। इसमें बिल्कुल स्पष्टता है कि महागठबंधन में प्रक्रिया के तहत चीजें हो रही हैं। सारी पार्टियों को मिलाकर मीडिया समूह बना है, सारी पार्टियों को मिलाकर घोषणापत्र समिति बनी है, सारी पार्टियां मिलकर सीटें तय करेंगी। वही कुमार ने दावा किया कि भाजपा 'आपदा में अवसर' ढूंढ रही है और नीतीश

कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर, इस पद पर अपना चेहरा लाने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वे नीतीश जी के अस्वस्थ होने पर यह कोशिश कर रहे हैं। वह पहले भी प्रयास कर चुके हैं। भाजपा पिछले कई दशकों से बिहार में वही करना चाहती है जो दूसरी जगह करने में सफल रही है। मतलब पहले क्षेत्रीय दल का साथ पकड़ो और फिर धीरे-धीरे उसे निगल जाओ। बिहार में ऐसा न कर पाने की वजह से भाजपा नीतीश का साथ लेने को मजबूर हुई। कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने कहा था कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। तो क्या नीतीश जी ब्लूटूथ से (राजग में) डाउनलोड हो गए? उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन, बेरोजगारी, पेपर लीक, परीक्षाओं का समय पर नहीं होना, अपराध में वृद्धि और नौकरशाही की मनमानी आदि प्रमुख मुद्दे होंगे। उनका कहना था कि भाजपा बिहार में 'ऑपरेशन सिंदूर' के मुद्दे को ज्यादा नहीं उछाल रही है क्योंकि उसे पता है कि बिहार के लोग सेना को लेकर राजनीति पसंद नहीं करेंगे। वही कन्हैया कुमार ने खुद के विधनसभा चुनाव लड़ने से जुड़े प्रश्न पर क्रिकेट की शब्दावली का इस्तेमाल किया और कहा कि जैसे बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण सभी अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं जिन्हें क्रिकेट के मैदान में निभाना पड़ता है, उसी तरह राजनीति में चुनाव लड़ना भी एक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना, दूसरों को चुनाव लड़वाना, प्रचार करना, ये सभी जिम्मेदारियां हैं जो पार्टी देती है। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। पहले भी, जब मैंने चुनाव लड़ा था तो यह पार्टी के आदेश पर ही लड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर कप्तान मुझसे बाहर बैठने और क्रीज पर मौजूद लोगों के लिए ड्रिंक पहुंचाने के लिए कहते हैं, तो मैं यह करूंगा। और अगर कप्तान मुझसे कहते हैं, तो





मैं पैड पहनकर बल्लेबाजी भी करूंगा।

गौरतलब है कि बिहार में 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों ने इस वर्ष के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक करीब 6 घंटे तक चली। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हां, सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन मैं अभी और विवरण नहीं दे सकता। विचार-विमर्श एक आंतरिक मामला है और जब चीजें अंतिम रूप ले लेंगी, तो हम इसे सार्वजनिक कर देंगे। उनके 'इंडिया' गठबंधन के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होने की संभावना है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता ने यह भी आरोप लगाया कि जद(यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार "नकलची" है जो युवा आयोग के गठन और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने जैसे उनके विचारों को चुरा रही है। तेजस्वी ने कहा कि मुझे यकीन है कि 'माई बहिन सम्मान योजना' भी जल्द ही उनके द्वारा नकल कर ली जाएगी। उन्होंने वादा किया है कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर वह राज्य की महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक भत्ता देंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि लोग राजग सरकार से तंग आ चुके हैं, जिसमें "दूरदर्शिता" का अभाव है और वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है। उनका ध्यान जब इस ओर आकृष्ट कराया गया कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जैसे राजग सहयोगी भी बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करने लगे हैं, तो राजद नेता ने पलटवार करते हुए कहा, "उन्हें केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि बिहार में 'जंगल राज' है।" 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के अध्यक्ष मुकेश सहनी और तीन वाम दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद सहनी ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा,

"हां, सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है। हम अभी इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं कर सकते।



लेकिन यह कहना चाहूंगा कि अन्य मुद्दे भी थे, जैसे समन्वय समिति का गठन करना और यह

सुनिश्चित करने की रणनीति कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कोई गड़बड़ी न हो। सहनी ने कहा कि हम एसआईआर के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन जब तक उच्चतम न्यायालय अंतिम फैसला नहीं सुना देता, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस कवायद के दौरान सभी निर्देशों का पालन किया जाए।" सहनी ने 2020 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन एक साल के भीतर ही भाजपा से उनका नाता टूट गया। बॉलीवुड सेट डिजाइनर रह चुके सहनी से यह भी पूछा गया कि क्या इस बारे में निर्णय लिया गया है कि यदि तेजस्वी शीर्ष पद पर आसीन होते हैं तो उपमुख्यमंत्री कौन होगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी नहीं छिपाने वाले सहनी ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, "और कौन, मेरे सिवा।"

बताते चले कि बिहार में चुनाव के पहले राजनीतिक दलों के बीच डिजिटल वार



मुकेश सहनी



शुरू हो गया है। एआइ के सहारे एक दूसरे के पोस्टर बना आरोप-प्रत्यारोप साधे जा रहे हैं। अपने शासन काल में आइटी को आइटी-वाइटी क्या होता का जुमला कहने वाले राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने लगातार डिजिटल तरीके से एनडीए पर हमला बोल रहे हैं। वहीं भाजपा ने पोस्टर के सहारे रोजगार और सामाजिक पेंशन के सहारे तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद ने 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्लीवरी बाँय बताकर डिजिटल सियासी वार शुरू किया था। अब एआइ के आधार पर लालू प्रसाद ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें नीतीश कुमार के हाथ में दिये पंपलेट दिये गये हैं। वहीं पीएम मोदी के हाथ में केंद्र की सत्ता बचा रहे हैं, बिहार को सत्ता रहे हैं का पर्चा डाला गया है। बता दें कि लालू प्रसाद के सोशल मीडिया हैंडल से एआइ आधारित उनके चेहरे से मिलती जुलती एक तस्वीर जारी की गयी है। इसमें लालू प्रसाद की तरह दिखने वाला व्यक्ति उनके ही आवाज में उनकी वैचारिक छवि को उभारते हुए कहता है, जहां समानता और न्याय नहीं होता, वहां लोकतंत्र फल-फूल नहीं सकता। सत्ता पर नियंत्रण नहीं होता और न्याय कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित रहता है। वीडियो में चरवाहा विद्यालय की चर्चा करते हुए लालू की छवि को गांव-गरीब, दलित-पिछड़ा समाज के मसीहा के तौर पर पेश किया गया है। इसमें लालू का चेहरा लिये तस्वीर बोलता है, मैंने संदेश दिया मवेशी चराने वालों, मैला ढोने वालों, झाड़ू देने वालों, कपड़ा धोने वालों पढ़ो-लिखो, यही तुम्हारा उद्धार करेगा। इधर, भाजपा ने भी पोस्टर जारी किया। इसमें लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के अलावा तेजस्वी यादव के बीच आपसी संवाद दिखाया गया है। पहले पोस्टर में नवंबर 2025 की सूचना प्रश्नचिन्ह देते हुए सूचना टंगी है। इसमें लिखा गया है कि राघोपुर से तेजस्वी चुनाव....। इस पोस्टर में लालू

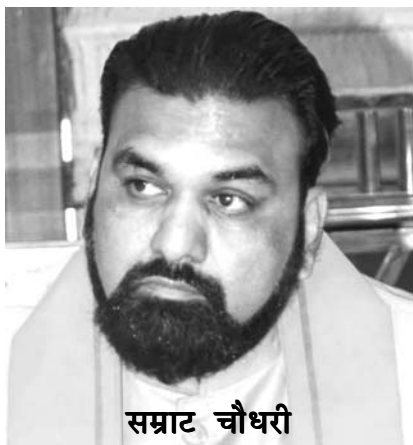


और राबड़ी उदास चेहरे लिये

तेजस्वी से कह रहे हैं, हम लोगों को 11 सौ रुपया पेंशन भी मिलता है, तुम क्या करोगे। दूसरे पोस्टर में एनडीए जॉब डेस्क दर्शाया गया है, जिसमें एक करोड़ नौकरी, मेडल लाओ-नौकरी पाओ और स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी गयी है। तेजस्वी इसमें कह रहे हैं कि हमको तो डिग्री भी नहीं है, कैसे लाभ मिलेगा। तीसरे पोस्टर में नियोजन केंद्र का चित्रण किया गया है। इसमें मेडल लाओ-नौकरी पाओ की सूचना को लेकर युवाओं की कतार लगी है। इसमें तेजस्वी कतार में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे पास तो डिग्री भी है। इधर, महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव का खबरों के सूत्र को लेकर की गयी टिप्पणी पर भाजपा ने तीखा हमला किया है। एक दिन पहले तेजस्वी

यादव ने मतदाता पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला था और उस पर सूत्रों के आधार पर गलत तथ्य देने का आरोप लगाया था। तेजस्वी यादव के उस बयान पर हमलावर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लालू प्रसाद के पुत्र यानी बड़बोले फिसड्डी लाल के बयानों में तिलमिलाहट, बौखलाहट, छटपटाहट और कंपकपाहट साफ देखी जा रही हैं। जब भी माइक पर आते हैं तो उनके चेहरे पर घबराहट और उनकी आवाज में कंपकपाहट दिखने लगती है। इसके पीछे एक गंभीर कारण यह है कि उन्हें अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। साथ ही हार का ठीकरा उनके अपने सिर पर फूटने का दबाव है। दूसरा कारण उन्होंने बताया, विरासत की सियासत में पार्टी कब्जियाने की तेजस्वी की व्याकुलता ने परिवार में खरमंडल पैदा कर दिया है। सम्राट ने लिखा, इसलिए लूट के लिए एकजुट हुए यह लोग चाहे कितना भी झूठ का लिबास ओढ़ लें, अगले कुछ महीनों में इनके बीच फूट तय है। वही भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ० निखिल आनंद कहते हैं, अगर तेजस्वी यादव सूत्र को मूत्र मानते हैं, तो हम सब भी तेजस्वी यादव के ज्ञान को कचरा





सम्राट चौधरी



डॉ० निखिल आनंद



डॉ० संतोष सुमन

ही मानते हैं। तेजस्वी से ऐसी गलतियाँ इसलिए संभव हैं क्योंकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की है। इसलिए उनका शब्दकोष सीमित है और अगर वो किसी विषय पर ज्यादा बोलेंगे या अपने ज्ञान का बखान करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी पोल खुलनी तय है। डॉ० निखिल ने कहा कि अब तेजस्वी कब तक मनोज झा से मौखिक और लिखित ज्ञान उधार लेकर खुद को ज्ञानी साबित करते रहेंगे? देर-सवेर उनकी पोल तो खुलनी ही थी। राहुल गांधी ने भी समय-समय पर काफी ट्यूशन लिया है, जो समय-समय पर उनके आधे-अधूरे एवं अधकचरे बातों के रूप में सामने आती रहती है। ज्ञान के मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की विषयवस्तु, गुण, प्रकृति एक जैसी है और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वही हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लघु जल संसाधन मंत्री डॉ० संतोष सुमन ने कहा है कि राजद और कांग्रेस पूरे देश में अराजकता फैला कर ऐन-केन-प्रकारेण सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए इन पार्टियों की कोशिश देश की हर एक सवैधानिक संस्था पर अविश्वास पैदा कर जनता को भड़काना है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश रूंगटा ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाना विपक्ष की

घबराहट और उनकी हार की हताशा को उजागर करता है। रूंगटा कहते हैं, मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक सवैधानिक प्रक्रिया है। हार के डर के कारण राजद के नेता गाली-गलौज व हल्की बयानबाजी पर उतर आए हैं। विपक्ष दबाव बनाकर इस कोशिश में लगा है कि देश के बाहर से आए ऐसे लोग जो येन-केन-प्रकारेण अपना आधार व राशन कार्ड तक बनवा लिया है, उनका नाम वोटर लिस्ट से न कट जाए।

बहरहाल, मतदाता सूची का पुनरीक्षण पर राजनीतिक रोटी सेकने में जुटी महागठबंधन नेताओं को एनडीए के नेता एक के बाद एक सामने आकर जवाब दे रहे हैं। वही विपक्ष सरकार के किसी भी कार्य पर सवाल उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। अलबत्ता चुनाव की नजदीकियों के बीच जनता में विपक्ष खुद को साफ सुथरा बताकर सत्तापक्ष के विकास कार्यों को नौटंकी बता रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए घटक दल के लोकप्रिय नेता चिराग पासवान एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए परेशानी बढ़ाते दिख रहे हैं। बता

दें कि केंद्रीय मंत्री और लोजपा मुखिया चिराग पासवान के बयान ने फिर बिहार की सियासी हवा को गर्मा दिया है। चिराग ने बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हनुमान अपने बयानों से नीतीश कुमार और एनडीए की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही गृह मंत्रालय भी है। यानी चिराग का यह हमला सीधे मुख्यमंत्री पर है। चिराग पासवान ने बिहार में हो रहे लगातार हत्याओं को लेकर भी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बिहार में हर तरफ हत्या, लूट और अपहरण जैसे अनेक गंभीर अपराध हो रहे हैं। जिसको लेकर हमें चिंता हो रही है। चिराग ने कहा कि नालंदा के बिहाशरीफ में 16 वर्षीय हिमांशु पासवान



अन्नू कुमारी, मृतका





और 20 वर्षीय अनु कुमार की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है, यह कहते हुए कि यह जघन्य घटना दिखाती है कि बिहार में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ढह गई है। हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो बिहार में हो रही हत्या और अपहरण जैसे संगीन अपराधों को कैसे सह सकते हैं। इसलिए हम बिहार सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि सरकार इन चीजों पर जल्द से जल्द रोक लगाए। चिराग के सरकार विरोध

ी बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में राक्षस राज है। राज्य में हो रही अराजकता, हत्याओं और अपराधों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी भाजपा और सीएम नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं, अपराधी जेलों से रिहा हो जाते हैं। हमें राज्य में ऐसी निष्क्रिय सरकार नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की कोई विचारधारा नहीं है। जो भी हैं, वे अभिनय करने वाले कलाकार हैं। तीन बार सांसद और केंद्रीय मंत्री

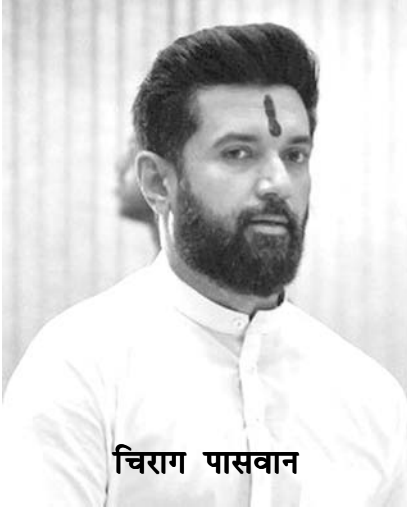
रहते हुए उन्होंने बेतुकी बातें कहने के अलावा कोई काम नहीं किया है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए अधिवास नीति शुरू करने की मांग का भी समर्थन किया। चिराग ऐसी मांग करने वाले बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पहले नेता बन गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक

बिहार के युवाओं के हित में सरकारी नौकरियों में अधिवास नीति लागू करने का समर्थन करता हूँ। नौकरी चाहने वालों की यह लंबे समय से मांग रही है।” उन्होंने दावा किया कि मैं आपको बता दूँ कि अधिवास नीति 2006 में लागू की गई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद विपक्षी दलों ने इसे वापस ले लिया। राजद और कांग्रेस कभी राज्य के युवाओं की बेहतरी के बारे में नहीं सोचते। वे हमेशा लोगों को गुमराह करते हैं। अगर वे सत्ता में आते हैं, तो वे विरासत कर के जरिए आपकी आधी से अधिक संपत्ति हड़प लेंगे। नीतीश कुमार नीत सरकार ने पहले ही अधिवास नीति लागू करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ऐसा कोई भी कदम संविधान के खिलाफ होगा। चिराग ने राजद पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जो लोग अब बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, जिन्होंने 90 के दशक में राज्य को बर्बाद कर दिया था।

गौरतलब है कि बिहार में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने अभी मतदान की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एनडीए के सहयोगी लोजपा मुखिया चिराग पासवान ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सियासी गलियारों में नई हवा चला दी है।

चिराग पासवान के इस बयान से राजग गठबंधन के अंदर मतभेद के संकेत आसानी से देखे जा सकते हैं। चिराग पासवान के बड़े ऐलान ने एनडीए नेताओं में हड़कंप मचा दी है। हुआ यूं है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वे बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख





चिराग पासवान

चिराग पासवान ने सारण जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। मीडिया खबरों के मुताबिक चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हर सीट पर चिराग पासवान खड़ा होगा। चिराग पासवान बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं। वे अलग-अलग सामाजिक संगठनों की सभाएं कर रहे हैं। बीते दिनों चिराग पासवान ने नालंदा में भव्य रैली की थी। इसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। उसके बाद से लगातार उनके बिहार में सियासी दौरे जारी हैं। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मैं सारण से घोषणा

कर चुका हूँ कि हां, चिराग पासवान बिहार के बेहतर भविष्य के लिए चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने कहा कि मैं बिहार के लोगों, अपने भाइयों, माताओं, अपनी बहनों के लिए चुनाव लड़ूंगा। हम बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जो सही मायने में राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाएगी। मैं अपने पिता के सपनों को साकार करूंगा और 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' के लिए काम करूंगा। मैं बिहार और उसके लोगों के लिए जिकूंगा और मरूंगा। वही चिराग पासवान अलग-अलग सामाजिक संगठनों के साथ सभाएं भी कर रहे हैं। फिलहाल केंद्र की राजनीति से अलग बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व चिराग पासवान के द्वारा नालंदा में भव्य रैली का आयोजन किया गया था। इसमें कार्यकर्ताओं का जनसमूह उमड़ा था। उसके बाद से लगातार बिहार के विभिन्न



जीतन राम मांझी

ने फेसबुक पर लिखा कि पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गंधारी और महाराज शकुनी जैसे सब मौन रहे, तब अभिमन्यु, जिसमें अनुभव की कमी थी, चक्रव्यूह में कूदा। क्योंकि समय का मान रखने के लिए अनुभव नहीं, नव-संकल्प चाहिए। उस पर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता ई० नंदलाल मांझी ने एक्स पर जवाब में लिखा, राजा ने एक बंदर को अपनी सुरक्षा में रखा। चूँकि बंदर अनुभवहीन था, इसलिए राजा को मक्खी से बचाने के लिए उसने राजा की ही गर्दन काट ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने आसपास हमेशा अनुभवी लोगों को रखना चाहिए। यह भी लिखा है कि वैसे इतिहास गवाह है, हर युद्ध में अभिमन्यु शहीद ही होता है।



अरूण भारती

जिलों में सियासी दौरे अनवरत जारी हैं। चिराग पासवान के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या वे बीजेपी और जेडीयू की सीट शेयरिंग के फार्मूले में शामिल नहीं होंगे? सनद रहे कि बिहार की राजनीति में सियासी बयानों के वाण तेज गति से छोड़े जाने लगे हैं। दलित लीडरशिप और सीटों की जोड़-गणित को लेकर एनडीए के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने-सामने हैं। दोनों नेताओं के बीच हुई बयानबाजी के बाद दोनों दलों के वरिष्ठ नेता इसमें कूद पड़े। दोनों दलों के बीच सभाओं से लेकर फेसबुक और एक्स पर सियासी जंग छिड़ गयी है। लोजपा रामविलास के सांसद चिराग पासवान के बहनोई अरूण भारती और हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी के बीच वार-पलटवार हुआ। लोजपा रामविलास के सांसद अरूण भारती



ई० नंदलाल मांझी



प्रशांत किशोर

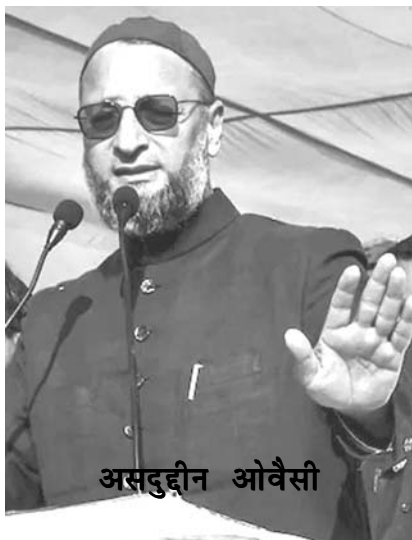
हालांकि एनडीए के घटक लोजपा, रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले खुद के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान देते रहे हैं। चिराग के कानून व्यवस्था पर उठाये गये सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने प्रतिक्रिया दी थी। कहा था कि गठबंधन में रहकर गुड़ खाना और गुड़अम्मे से परहेज यह ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करना ज्यादा भी मुश्किल नहीं। दरअसल, चिराग पासवान और हम पार्टी के बीच सियासी अदावत के कई कारण हैं। इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव से ही हुई है। जीतनराम मांझी और चिराग पासवान खुद को एक दूसरे से बड़ा दलित नेता बताने की होड़ में हैं। लोकसभा चुनाव में एक सीट मिलने से ही नाराज मांझी विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें चाहते हैं। लोजपा भी अपनी ताकत बढ़ानी चाहती है। इस सियासी जुबानी जंग के पीछे अधिक सीटें पाना भी है। चिराग पासवान जहां राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का संकेत देकर एनडीए के भीतर अधिक सीट झटकना चाहते हैं। वहीं, जीतन राम मांझी को आशंका है कि चिराग के दबाव में आखिरी वक्त में उनके हिस्से की सीटों में कटौती नहीं हो।

बहरहाल, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में चुनाव आयोग की टीम भी इस वक्त राज्य में डटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आयोग आखिर किन कारणों से दो दशक बाद, यानी 2003 के बाद पहली बार, एक विशेष और गहन मतदाता सूची संशोधन (इंटेसिव रिविजन) अभियान चला रहा है। चुनाव से पहले तमाम मुद्दों को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत

किशोर ने एक निजी चैनल से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार तक पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि इसकी पृष्ठभूमि समझने की जरूरत है क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह की ड्राइव चलाई गई। 2003 के बाद इस तरह की ड्राइव इलेक्शन के ठीक दो तीन महीने पहले चुनाव आयोग नहीं करता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में लोग बताते हैं कि इस तरह का ड्राइव चलाया गया और वहां जो परिणाम आए, कुछ लोगों का खासकर मुख्य विपक्ष कांग्रेस का, राहुल गांधी का, ऐसा मानना है कि इलेक्टोरल रोल के रिविजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो जांच का विषय हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि एक एक वर्ग में कम से कम ये बात बनी है कि चुनाव से तीन महीने पहले इस तरह का ड्राइव क्यों चलाया जा रहा है और अगर चलाया जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है की इलेक्शन

कमीशन को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे इश्योर किया जाएगा और जितने भी स्टेक होल्डर हैं चुनाव लड़ने, लड़ाने वाले, वोटर, इन सबको ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया कराई जा रही है, ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए है। किसी एक वर्ग को या किसी एक दल के समर्थकों या विरोधियों को हटाने या जोड़ने के लिए नहीं है। वही दूसरी ओर उन्होंने तेजस्वी यादव की 'कलम यात्रा' पर तंज कसा है। ज्ञात हो कि पटना में हाल ही में तेजस्वी यादव ने छात्र संसद का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हजारों छात्रों को 'कलम' बांटी और शिक्षा सुधार के वादे किए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी पार्टियों को ये अधिकार है कि वो अपने वोटर्स को या जो उनको सुनने को तैयार हैं, उनके सामने अपनी बात रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तेजस्वी यादव शिक्षा की बात करते हैं तो बिहार की जनता को समझना है कि 15-50 साल उनके मां-बाबू जी की आरजेडी की सरकार थी। शिक्षा व्यवस्था का उन 15 साल (1990 से 2005) में जितना नुकसान बिहार में हुआ है, शायद ही किसी दौर में हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि 3 साल तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के तौर पर रहे हैं और सरकार की कमान बहुत हद तक उनके हाथ में थी और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया? अभी पिछली जो सरकार अभी महागठबंधन की थी, उसमें शिक्षा मंत्री आरजेडी का ही था, उस समय शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया? लोग वो देख लें।





असदुद्दीन ओवैसी



प्रशांत किशोर



अरविंद केजरीवाल

रह गई बात कलम बांटने की तो हम लोग इसका विरोध करते हैं कि आप कलम बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं और लोगों का वोट लेते हैं। कलम बांटने से लोगों का भला थोड़ी होगा। आप अगर बांट सकते हैं तो ज्ञान बांटिए, शिक्षा बांटिए, रोजगार बांटिए। कलम बांटकर लोगों को लुभाने का प्रयास करना है, ये तो बहुत सिम्बोलिक चीज है, उसका कोई महत्व नहीं है। साथ तेजस्वी यादव द्वारा बार-बार जंगलराज शब्द के इस्तेमाल पर प्रशांत किशोर ने कहा, यह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि हाईकोर्ट के जजों ने कहा था कि 90 के दशक के अंत तक बिहार में जंगलराज था। यह तथ्य है कि उस दौर में हत्या, अपहरण, रंगदारी चरम पर थी। पटना से व्यापारी पलायन कर रहे थे। अगर तेजस्वी यादव उस दौर को सुशासन बताते हैं, तो जनता को समझ जाना चाहिए कि वे किस दिशा में बिहार को ले जाना चाहते हैं। आगे पीके ने नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति अब ऐसी नहीं है कि वह मुख्यमंत्री बन रह सकें। जो व्यक्ति स्टेज पर बैठकर प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो कि उनके बगल में बैठे हैं। उस व्यक्ति से आप अपेक्षा करते हैं कि वो बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट का लीडरशिप लेके चले। अगर ये बात आपको पता है, हमको पता है, बिहार के सामान्य लोगों को पता है तो ये कैसे संभव है कि अमित शाह और मोदी जी को पता नहीं है। उन्हें भी पता है, लेकिन जो राजनीतिक मजबूरियां हैं उनकी, भाजपा का अपने दम पर चुनाव लड़ने की ना तैयारी है, ना दम है। तो उनको अभी लड़ना है

नीतीश कुमार के साथ। अगर गलती से सत्ता आ गई हाथ में तो नीतीश को हटाकर बीजेपी अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार अब न सरकार चला रहे हैं, न पार्टी चला रहे हैं और न ही एनडीए गठबंधन। सब कुछ भाजपा और अमित शाह चला रहे हैं।

दिलचस्प है कि बिहार के चुनावी दंगल में मुकाबला सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन के बीच माना जा रहा है, लेकिन कुछ और दल भी हैं जो मुकाबला बहुकोणीय बनाने की कोशिश में हैं। ऐसी पार्टियों की लिस्ट में चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर (पीके) की जन सुराज के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम तक के नाम हैं। क्या ये पार्टियां बिहार चुनाव में इम्पैक्ट प्लेयर साबित हो पाएंगी? तो बता दें कि प्रशांत किशोर एक सफल चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को अकेले पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की जीत के शिल्पकार माने जाने वाले पीके 2015 के बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत के भी रणनीतिकार रहे। पीके की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता विरोधी दल खारिज करते आए हैं, लेकिन चुनाव करीब आते ही जन सुराज की रणनीति ने एनडीए और महागठबंधन, दोनों को उलझा दिया है। बिहार में 25 साल से कम उम्र के युवाओं की आबादी करीब 57 फीसदी है और पीके की पार्टी भी युवाओं पर फोकस करके ही चल रही है। जातियों के मकड़जाल में उलझी बिहार की राजनीति में बदलाव की बात कर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी रोजगार और पलायन

के साथ ही शिक्षा जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उठा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के कथित पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन में पीके की सक्रिय भागीदारी को भी युवाओं के बीच जन सुराज की सियासी जमीन बनाने की रणनीति के रूप में ही देखा गया। कभी एनडीए का कोर वोटर रहे युवाओं के बीच पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी अच्छा समर्थन मिला था। जातीय गणित की बात करें तो प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। राजपूत चेहरे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दलित नेता मनोज भारती प्रदेश अध्यक्ष। सवर्ण और दलित चेहरे संगठन में शीर्ष पदों पर हैं। पीके की नजर कुर्मी और मुस्लिम मतदाताओं पर भी है। सवर्ण, कुर्मी और दलित मतों में पीके संघ लगा पाए तो नुकसान एनडीए को होगा। मुस्लिम और युवा मतदाताओं के बीच जन सुराज ने पैठ बनाई, तो यह आरजेडी और महागठबंधन के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने भी बिहार चुनाव में किसी से गठबंधन किए बगैर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया है। कुछ ही महीने पहले हुए दिल्ली चुनाव में हार के साथ केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी की फिलहाल पंजाब में सरकार है। आम आदमी पार्टी की चुनावी राह में बिहार का अलग सियासी मिजाज और जातीय गणित के साथ ही लोकल लेवल पर बड़े कद के परिपक्व नेताओं की कमी मुश्किलें उत्पन्न कर सकती हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी बिहार में शिक्षा के दिल्ली मॉडल, मोहल्ला

क्लिनिक जैसी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। हालांकि, आम आदमी पार्टी बिहार के शहरी इलाकों और युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय भी है। आम आदमी पार्टी करीबी फाइट वाली सीटों पर अंतर उत्पन्न कर सकती है। वही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार के मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में मजबूत पकड़ रखती है। ज्ञात हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी को 1.13 फीसदी वोट मिले थे तथा पांच सीटों पर उसके उम्मीदवार जीते थे। चार सीटों पर पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। चुनाव से पहले चल रहे वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण और सत्यापन के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच शिकायत दर्ज कराने वाले असदुद्दीन ओवैसी प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर भी मुखर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी का कोर वोटर मुस्लिम है, जो आरजेडी के एम-वाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण का भाग है। ओवैसी की पार्टी के उतरने से आरजेडी को मुस्लिम वोट का नुकसान हो सकता है। दिगर बात है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, ये तीनों पार्टियां कई सीटों पर एनडीए और महागठबंधन का चुनावी गणित बिगाड़ सकती हैं। पीके की पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने के बाद एनडीए के सामने अपने वोट बैंक को एकजुट बनाए रखने की चुनौती होगी। ओवैसी की पार्टी महागठबंधन की राह मुश्किल कर सकती है। आम आदमी पार्टी युवा वोट बैंक में संघ लगा पाती है, तो चुनौती दोनों गठबंधनों के

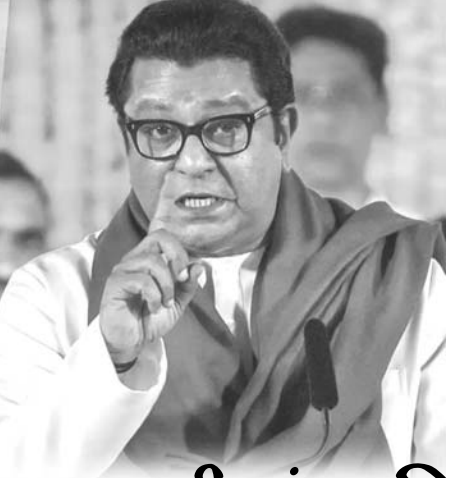


लिए कड़ी होगी। ये दल कितनी सीटें जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, यह अलग विषय है लेकिन इतना जरूर है कि करीबी लड़ाई वाली सीटों पर इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका जरूर निभा सकते हैं।

बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव को विपक्ष में बैठना पड़ा था। एक बार फिर विधानसभा चुनाव में उनकी अग्निपरीक्षा होने वाली है। चूँकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, ऐसे में पार्टी और महागठबंधन का पूरा भार उन्हीं के कंधों पर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिहार में कितना जादू चलेगा, यह कहना फिलहाल मुश्किल है। पिछले चुनाव में महागठबंधन में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था। कांग्रेस 70 में से सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। दूसरी ओर सत्ता पक्ष में एक से एक दिग्गज और भीड़जुटाऊ नेता हैं। स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, चिराग पासवान समेत और भी कई ऐसे नेता हैं, जो अपना प्रभाव रखते हैं। इस बार चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर भी मैदान में होंगे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वे किसका खेल खराब करेंगे। इस बार एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी विपक्षी गठबंधन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वे महागठबंधन में रहेंगे, इसका फैसला होना अभी बाकी है। ओवैसी की पार्टी ने पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती थीं। ऐसे में उन्हें कमतर नहीं माना जा सकता। हालांकि तेजस्वी को अपने

एम-वाय (मुस्लिम-यादव) समीकरण पर पूरा भरोसा है, लेकिन उनकी राह आसान नहीं रहने वाली है। क्योंकि उनके अपने भाई तेजप्रताप भी उनसे नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वे अपने भाई यानी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार हैं। लालू यादव ने भी उन्हें इस पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि, महागठबंधन में अन्य दलों विशेषकर कांग्रेस के भीतर इस पर पूरी सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। कांग्रेस के कुछ नेता अभी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी ओर, वामपंथी दलों को तेजस्वी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही नीतीश कुमार की राजनीतिक अस्थिरता और पाला बदलने की प्रवृत्ति बिहार में एनडीए को मतदाताओं की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद को लेकर आने वाले समय खासकर चुनाव के बाद खींचतान की प्रबल संभावना है। नीतीश की वर्तमान स्थिति तेजस्वी को फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन, आगामी चुनाव उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान आदि दिग्गज नेताओं के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाएंगे? क्योंकि बिहार चुनाव में न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। भाजपा और जेडीयू चुनाव जीतने के लिए पूरा दम लगाएंगे और कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। ●





मलेच्छ ठाकरे बंधु, कर रहे बढनाम मराठी संस्कृति

● संजय कुमार सिन्हा

मराठी स्वभाव मराठी गौरव को निचा करता ये ठाकरे परिवार, कभी बाल ठाकरे कार्टून बना कर पत्रकारिता करने आये

थे, बाल ठाकरे कुछ समुह को जुटाने में कामयाब हो गये थे, परंतु उन्होंने मराठी सेना नहीं बनाई थी? शिवसेना बनाई थी, बाल ठाकरे शिवसेना के बैनर तले हिन्दुओं को जोड़ने का योजना बनाई थी परंतु उन्होंने ऐसा कर नहीं पाये, उन्होंने बोम्बे शहर से दक्षिण भारतीय (साउथ इंडियन) के विरुद्ध मार पीट, भगाना एक नफरत की योजना पर काम किये फिर उन्होंने ऐसी ही योजना गुजराती बंधुओं के लिए किया बाद के समय में उतर भारतीय बंधुओं को मार पीटाई रोजगार के नाम पर भगाने का योजना शुरू किया। बाल ठाकरे अपने जीवन में ही अपने बेटों को संयोग कर एक नहीं रख पाये और अपने खास भतीजा राज ठाकरे जो कभी शिवसेना के दूसरे सबसे बड़े ठिकेदार बने थे वो राज ठाकरे भी बाल ठाकरे के जीवन काल में ही अलग हो गया और एक पार्टी बना ली, सबसे बड़ा मजाक लगता है राज ठाकरे के दल का नाम उसने अपने राजनीतिक दल का नाम रखा (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) जैसे लगता हो महाराष्ट्र कोई राष्ट्र या राज्य है ही नहीं? ये अब अपने सेना से महाराष्ट्र का जन्म या महाराष्ट्र को आस्तित्व में लायेंगे? राज ठाकरे के अलग होने और आधारहीन राजनीति के कारण ये व्यक्ति शुरू से हासिये पर रहा, इसके व्यक्ति विशेष एक आध विधायक और निगम पार्षद बने, इसकी महाराष्ट्र की राजनीति में दाल

तो गल नहीं रही थी, कभी बीजेपी से करीबी तो कभी कुछ और इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रही थी कि करें तो क्या करें? फिर वही घिसा पीटा योजना इस बार इसने भाषा के नाम पर मार पीट करने लगा उसमें भी सिर्फ उतर भारतीयों के

हाँ ये जरूर है कि महाराष्ट्र में इसने सीटें जीती जरूर है, क्या हिन्दी के बीना हिन्दू का साधा जा सकता है? आज भी अरब देशों में भारतीय मुसलमान को हिन्दू ही कहा जाता है, संस्कृत से हिन्दी मराठी भोजपुरी सभी का विस्तार या कहें

कि जन्म हुई है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मराठी भाषा कोई कम है या खराब है, सभी भाषा अपनी संस्कृति को बचाने की पहली पिलर होती है, परंतु उतर भारतीय भोजपुरी भाषा की एक देश ही है जिसे मोरिशस कहते हैं, क्या मराठी भाषा दो चार प्रदेशों के आलावा कहीं नहीं बोली जाती होगी परंतु हिन्दी समस्त राष्ट्र में बोली जाती है साथ साथ परोसी देशों में भी नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान एवं श्रीलंका भुटान वर्मा जैसे देशों में बोलने समझने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। यह ठाकरे बंधुओं को मराठीयों के आर्थिक स्थिति पर तरस नहीं आती कि कभी भारत के आन बान शान मराठा आज अपने लिए आरक्षण की मांग और आंदोलन हमेशा करते रहती है, अखंड भारत के शिरमौर रहे क्षत्रपति शिवाजी महाराज संभाजीराव उनके उतरधिकारी आज सड़क पर महज सरकारी नौकरियों के लिए आंदोलन कर रहीं हैं? तो क्या ये मराठी के ठेकेदार इसके जिम्मेवार नहीं है? उतर भारतीय हो या समस्त भारतीय वो



साथ और जा मिला अपने हारे हुये थके- पिटे भाई उद्धव ठाकरे से जो खुद का खानदानी पार्टी से हाथ धो चुका है, इन दोनों भाईयों को न तो महाराष्ट्र से मतलब है और न ही मराठियों से भाषा तो बहुत दूर की बातें हैं? ये बाल ठाकरे के कुनबे अपने को हिन्दू हृदय सम्राट मानने का प्रयास करता रहा है पर ऐसा कभी हो न सका,

छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आर्दश मानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छह सरसंघचालकों में से चार महाराष्ट्र के ही थे या है, कभी कोई उतर भारतीय को को इसके लिए कोई शिकायत रहा क्या? उतर भारतीय मानुष मराठी तमिल तेलुगु बंगला सभी को प्यार करते हैं और अपना मानते हैं, ऐसा नहीं है कि मराठी



लोग उत्तर भारतीयों से नफरत करते हैं वो भी प्यार करते, कभी कोई भी मराठी को किसी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के लोगों से कोई परेशानी नहीं रहीं हैं, ये सिर्फ तुक्का और राजनीति

के दुकान को कैसे चलाई जाये ऐसे नेता उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी आमजनता मराठी को इससे कोई लेना देना नहीं है, मुम्बई पहले की

तरह मुम्बई अगर किसी एक चीजों के लिए मशहूर है तो वह है हिन्दी फिल्म उद्योग, क्या मराठी मानुष कभी चाहेगें की हिन्दी फिल्म नगरी महाराष्ट्र व मुम्बई से हटा दी जाये? कभी शिवसेना के बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश बिहार से हुआ करते थे आज भी इनकी राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी उत्तर भारतीय हैं, कभी संजय निरुपम वगैरह भी बिहार से आये हुये नेता ही थे, ऐसे तो बाल ठाकरे के पूर्वजों भी बिहार से महाराष्ट्र आये थे, आज उद्धव ठाकरे अपने लालच और पुत्रमोह में कहीं का न रहे न पाट्री का नाम बचा न ही जनता का समर्थन राज ठाकरे तो पहले से ही हाशिये पर है, ये राज ठाकरे तो कमजोर व्यक्तियों को मारपीट करता रहा है, ये ठाकरे के वंशज बहुत पढ़े लिखे नहीं रहे हैं, जिस उत्तर भारतीय को भगाने की बात करता है ठाकरे बंधु अगर ये सिर्फ एक महीने काम करना बंद कर दे तो महाराष्ट्र की कारखाने बिलकुल बंद हो जायेंगे, ठाकरे बंधु कभी भी मराठी मानुष के हमदर्द नहीं थे और न हैं, क्या इस जाहिल बंधु को समझ नहीं आता कि कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है? उदाहरण बहुत से हैं जैसे- महात्मा गाँधी की हत्या इन्दिरा गाँधी की हत्या के बाद निर्दोष ब्राह्मण और निर्दोष सरदार की हत्या देश के विभिन्न शहरों में हुई थी, क्या ऐसा षड्यंत्र ठाकरे बंधु मराठी मानुष के लिए तो नहीं तैयार कर रही है? क्योंकि ऐसे नेता किसी के सगे नहीं होते, कभी हिन्दू के नेता बनना कभी सिर्फ मराठी के नेता बनना ये दोगलापन नहीं है क्या? सिर्फ मराठी मानुष की चिंता करने वाले बाल ठाकरे उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को समस्त भारत में फैलाया हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश बिहार में इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है? इन्होंने समुचे भारत में शिवसेना की ब्रांच खोल रखी है, भले इन्हें किसी प्रदेश में कोई कामयाबी नहीं मिली हो, आगे भी ठाकरे बंधु कोई कामयाब नहीं होने वाले है, क्योंकि इनकी प्रासंगिकता अब बची नहीं है, जिसे अब महाराष्ट्र के मानुष भी जान चुके हैं।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।



अखिलेश को बड़ा झटका देने की तैयारी में ब्राह्मण समाज

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

अजमगढ़, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो समाजवादी पार्टी (सपा) का गढ़ माना जाता है, 3 जुलाई 2025 को एक बार फिर सुर्खियों में था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने नए आवास और पार्टी कार्यालय, जिसे उन्होंने पीडीए भवन नाम दिया, का उद्घाटन और गृह प्रवेश किया। यह भवन अनवरगंज में 72 बिस्वा जमीन पर बना है, जिसमें अखिलेश का निजी निवास, पार्टी कार्यालय, और समर्थकों के लिए एक बड़ा हॉल शामिल है। लेकिन इस भव्य आयोजन के बीच एक सवाल ने सबका ध्यान खींचा अखिलेश ने गृह प्रवेश की पूजा के लिए काशी के ब्राह्मण विद्वानों को आमंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समुदाय के किसी विद्वान को क्यों नहीं बुलाया? यह सवाल न केवल सियासी गलियारों में, बल्कि सोशल मीडिया और स्थानीय जनता के बीच भी चर्चा का

विषय बन गया। बात ब्राह्मण समाज की नाराजगी की कि जाये तो ब्राह्मण सभा ने सपा कार्यालय और आवास के गृह प्रवेश के लिये गये ब्राह्मणों को अपने समाज से निकाल दिया है। ब्राह्मणों की यह नाराजगी सपा को 2027 के चुनाव में भारी पड़ सकती है, यूपी में करीब 10 प्रतिशत ब्राह्मण हैं।

आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का

यह नया कार्यालय 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अखिलेश ने इसे पीडीए भवन नाम देकर अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया। पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित, और अल्पसंख्यक सपा की राजनीतिक रणनीति का आधार रहा है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को 37 सीटें दिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजय रथ को रोकने में मदद की। अखिलेश ने उद्घाटन समारोह में

कहा, 'पीडीए की एकता ही हमें 2027 में सत्ता दिलाएगी।'

इस भवन को न केवल एक कार्यालय, बल्कि एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां युवाओं को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाएगा। लेकिन इस आयोजन की चमक उस समय फीकी पड़ गई, जब यह खबर आई कि अखिलेश ने गृह प्रवेश की पूजा के लिए काशी के ब्राह्मण विद्वानों को बुलाने की इच्छा जताई थी, लेकिन वे नहीं आए। सूत्रों के अनुसार, काशी के पंडितों ने इटावा में हाल ही में हुए एक विवाद, जिसे 'इटावा कथावाचक कांड' कहा





जा रहा है, के कारण नाराजगी जताते हुए पूजा कराने से मना कर दिया। इस कांड में अखिलेश के कुछ बयानों को ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ माना गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दान-दक्षिणा और पूजा-पाठ की परंपराओं पर सवाल उठाए थे।

अखिलेश ने अंततः स्थानीय पंडितों से पूजा करवाई, और कुछ स्रोतों के अनुसार, पुजारी चंदन कुशवाहा ने इस कार्य को संपन्न किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि पीडीए भवन के उद्घाटन जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर, जब अखिलेश अपनी पीडीए रणनीति को और मजबूत करने की बात कर रहे थे, तब उन्होंने पीडीए समुदाय के किसी विद्वान को पूजा के लिए क्यों नहीं चुना? यह सवाल न केवल उनके विरोधियों, बल्कि उनके समर्थकों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे अखिलेश की रणनीति में विरोधाभास बताया। एक यूजर ने लिखा, 'भवन का नाम तो रख दिया, लेकिन पूजा ब्राह्मणों से ही करवानी है। क्या पीडीए में कोई विद्वान नहीं था?' एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा, 'अखिलेश जी को कोई पीडीए का पंडित नहीं मिला क्या? कथनी और करनी में अंतर साफ दिखता है।' इन टिप्पणियों ने सपा के पीडीए

फार्मूले पर सवाल उठाए, जिसे अखिलेश ने हाल के वर्षों में अपनी पार्टी की छवि को यादव-मुस्लिम से हटाकर व्यापक बनाने के लिए अपनाया था। आजमगढ़ में पूजा के लिए ब्राह्मण विद्वानों को बुलाने की कोशिश को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश



शायद यह संदेश देना चाहते थे कि उनकी पार्टी सभी समुदायों को साथ लेकर चल रही है। लेकिन काशी के पंडितों की अनुपस्थिति और स्थानीय पंडितों द्वारा पूजा करवाने ने इस संदेश को कमजोर कर दिया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश का यह कदम उनकी पीडीए रणनीति को मजबूत करने

का प्रयास था, लेकिन यह उल्टा पड़ गया। इस आयोजन को और चर्चा में लाने वाला एक अन्य पहलू था ब्राह्मण महासभा और विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यों का विरोध। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अखिलेश के खिलाफ काले झंडे लहराए और उन पर ब्राह्मण समुदाय की छवि खराब करने का आरोप लगाया। इसके अलावा, एक सुरक्षा चूक ने भी सुर्खियां बटोरीं, जब एक युवक बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के करीब पहुंच गया। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया, लेकिन इस घटना ने अखिलेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। इन विवादों के बावजूद, पीडीए भवन का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भवन न केवल अखिलेश का दूसरा घर है, बल्कि पूर्वांचल में सपा की सियासी रणनीति का केंद्र भी बनेगा। अखिलेश ने अपने भाषण में बीजेपी पर जमकर हमला बोला और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय अपनी सरकार को दिया। उन्होंने कहा, लखनऊ से आजमगढ़ पहुंचने में उतना ही समय लगता है, जितना सैफई। यह हमारे द्वारा बनाए गए एक्सप्रेसवे की बदौलत है।

बहरहाल, आजमगढ़ में पीडीए भवन का उद्घाटन और गृह प्रवेश एक सियासी मास्टरस्ट्रोक हो सकता था, लेकिन ब्राह्मण विद्वानों की अनुपस्थिति और पीडीए समुदाय के विद्वानों





को न बुलाने का फैसला सवालियों के घरे में आ गया। जहां वे एक तरफ अपने मूल समर्थक वर्ग

को मजबूत करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ सवर्ण वोटों को भी साधने की कोशिश कर रहे

हैं। 2027 के चुनावों में यह रणनीति कितनी कारगर होगी, यह तो समय ही बताएगा। ●



इटावा में जाति के नाम पर धर्म का अपमान सनातन परंपरा हुई शर्मसार

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दादरपुर में घटित एक घटना ने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हलकों में उबाल ला दिया है। भागवत कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ कथित रूप से की गई अभद्रता, मारपीट और जातिगत अपमान ने न केवल सनातन परंपरा की आत्मा को झकझोरा है, बल्कि समाज की उस मानसिकता को भी उजागर कर दिया है, जो आज भी जातीय श्रेष्ठता के भ्रम में जी रही है। मुकुट मणि यादव का आरोप है कि वह गांव में श्रीमद्भागवत कथा कहने पहुंचे थे, जहां आयोजकों में से कुछ लोगों ने उनकी जाति पूछी। जब यह सामने आया कि वे यादव समुदाय से हैं, तो उनके साथ न केवल कथा रुकवा दी गई, बल्कि उन्हें मंच से हटाकर गाली-गलौज की गई, उनकी चोटी काटी गई, सिर मुंडवा दिया



गया और कथित तौर पर उन्हें महिला के सामने नाक रगड़वाकर माफी मांगने के लिए विवश

किया गया। आरोपों के अनुसार, उनके चेहरे पर पेशाब तक डाला गया और हारमोनियम तोड़ दिया गया। यह घटना कैमरे में कैद हुई और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, प्रदेशभर में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को जातिगत वर्चस्व की पराकाष्ठा बताते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लखनऊ में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अब कथा कहने के लिए जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य हो गया है, तो योगी सरकार को इस पर कानून बना देना चाहिए। उन्होंने मुकुट मणि यादव और संत सिंह यादव को सम्मानित करते हुए 21-21 हजार रुपये की राशि भेंट की और पार्टी की ओर से 51-51 हजार रुपये देने की घोषणा की। उनका कहना था कि यह घटना भाजपा शासित प्रदेशों में पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के प्रति निरंतर अपमानजनक व्यवहार का उदाहरण है। लेकिन जैसे-जैसे राजनीतिक हलचल



तेज हुई, यह मामला कई और मोड़ों पर जा पहुंचा। कथावाचकों के पक्ष में यादव महासभा, समाजवादी पार्टी और अन्य संगठन खड़े हो गए। वहीं दूसरी ओर, गांव की ही महिला रेनू तिवारी और उनके पति जयप्रकाश तिवारी सामने आए और कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाए। रेनू तिवारी का कहना है कि कथा के दौरान भोजन के समय कथावाचक ने उनकी अंगुली पकड़ने की कोशिश की, जिससे उन्हें असहजता हुई। उन्होंने तुरंत अपने पति को जानकारी दी और गांव के कुछ युवा आक्रोशित हो उठे। महिला पक्ष का दावा है कि कथावाचक ब्राह्मण बनकर गांव में पहुंचे थे और जब सच्चाई सामने आई, तो विवाद गहराया। आरोप लगाया गया कि कथावाचक ने फर्जी आधार कार्ड से अपनी जाति ब्राह्मण दर्शाई थी।

अब मामला एक नया मोड़ लेता दिख रहा है, जहां पीड़िता महिला की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की बात सुनकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। पुलिस ने अब तक चार लोगों आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, मनु दुबे और निक्की अवस्थी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथावाचकों से मारपीट की थी। हालांकि अब कथावाचकों के आधार कार्ड को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसमें एक ही फोटो पर अलग-अलग नाम और जाति दर्ज हैं। यह तथ्य पुलिस की जांच को और जटिल बना रहा है। इस घटनाक्रम के बाद ब्राह्मण महासभा ने भी मोर्चा खोल दिया है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे ने कहा कि कथावाचक समाज को गुमराह कर ब्राह्मण बनकर कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी महिला के साथ यदि छेड़खानी हुई है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि केवल एक पक्ष के आधार पर कार्रवाई की गई तो महासभा आंदोलन का रास्ता अख्तियार

करेगी। उनका तर्क है कि कोई भी कथा कह सकता है, लेकिन कथा की आड़ में दुर्व्यवहार की अनुमति नहीं दी जा सकती। इधर, समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम एक साजिश है, ताकि कथावाचकों को झूठे आरोपों में फंसाकर जातीय गोलबंदी को तोड़ा जा सके। सपा इटावा जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य का कहना है कि महिला की शिकायत विवाद के दो दिन बाद सामने आई, जब राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या यादव हिंदू नहीं हैं? क्या उन्हें कथावाचक बनने का अधिकार नहीं? उन्होंने कहा कि यह सब कुछ च्छ समाज को अपमानित



करने की साजिश का हिस्सा है। यह पूरा विवाद अब धर्म और जाति के उस चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है, जहां सनातन परंपरा के मूल विचारों की परख हो रही है। क्या कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है? अगर हम शास्त्रों और धर्मग्रंथों की ओर देखें तो स्पष्ट होता है कि ऐसा कोई विधान नहीं है। स्वयं महर्षि वेदव्यास, जिनके नाम पर व्यास पीठ की परंपरा है, वर्णसंकर थे। उनके पिता महर्षि पाराशर और माता मत्स्यगंधा (सत्यवती) थीं, जो निषाद कन्या थीं। सूत जी, जो भागवत पुराण के मुख्य वाचक माने जाते हैं, वे भी वर्णसंकर थे। शबरी एक वनवासी भीलनी थीं, लेकिन श्रीराम ने उनके

प्रेम को पूजा का सर्वोच्च रूप माना। व्याध गीता में एक शिकारी, एक ब्राह्मण सन्यासी को कर्मयोग का उपदेश देता है। प्रह्लाद दैत्यकुल में जन्मे थे, लेकिन उन्हें भक्तराज की उपाधि मिली। यह सभी उदाहरण इस बात का प्रमाण हैं कि सनातन धर्म में ज्ञान, भक्ति और साधना ही सर्वोपरि मानी गई है, जाति नहीं।

यदि मुकुट मणि यादव और संत सिंह यादव ने सच्चे श्रद्धा भाव से कथा कही, और उन्हें केवल जाति के नाम पर अपमानित किया गया, तो यह संपूर्ण सनातन परंपरा का अपमान है। लेकिन यदि महिला पर की गई अभद्रता के आरोप सही हैं, तो वह भी उतना ही निंदनीय है। ऐसे में न्याय तभी संपन्न होगा जब दोनों पक्षों की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। इस मामले ने यह भी दर्शाया है कि हमारी सामाजिक संरचना आज भी कितनी संवेदनहीन है। जब धर्म की बात आती है, तो हम पूजा-पाठ की आड़ में एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। यदि कथावाचक ने अपनी जाति छिपाई, तो यह गलत है, लेकिन यदि उन्हें जाति के नाम पर पीटा गया, नाक रगड़वाई गई, अपमानित किया गया, तो यह उससे भी बड़ा अपराध है। ऐसे व्यवहार से न केवल मानवता

अपमानित होती है, बल्कि समाज की वह बुनियाद भी हिलती है, जिस पर भारत का बहुलतावादी ढांचा टिका है। यह घटना राजनीतिक गलियारों में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जातीय समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है। समाजवादी पार्टी इसे 'पिछड़े वर्ग पर अत्याचार' के रूप में पेश कर रही है, जबकि भाजपा खेमे से जुड़े संगठन इसे ब्राह्मण विरोध के रूप में देख रहे हैं। यादव बनाम ब्राह्मण विमर्श को हवा देकर राजनीतिक दल अपने-अपने हित साधने में जुटे हैं, लेकिन इस संघर्ष में वह वास्तविक मुद्दा गुम होता जा रहा है समाज में समता, न्याय और धर्म के प्रति सम्मान। ●

मायावती ले सकती हैं आजम-ओवैसी का साथ



● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

3

उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही समीकरण

बदल

रहे हैं। मायावती, जो लंबे समय से दलित वोट बैंक की धुरी रही हैं, अब मुस्लिम वोटों को साधने की रणनीति पर काम कर रही हैं। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता आजम खान के बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के करीब आने की चर्चाएं तेज हैं। यह घटनाक्रम सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सियासी चुनौती बन सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी का आधार मुस्लिम और यादव वोटों पर टिका है।

मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बसपा की कमजोर स्थिति को देखते हुए अपनी रणनीति बदली है। उनकी पार्टी, जो

पुराने गठजोड़ को फिर से तलाश रही हैं। आजम खान, जो सपा के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम चेहरा रहे हैं, के बसपा के करीब आने की खबरें इस दिशा में एक बड़ा संकेत हैं। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सपा से दूरी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ उनकी मुलाकातें सियासी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आजम खान



कभी दलितों की एकमात्र आवाज थी, अब केवल एक विधायक तक सिमट गई है। ऐसे में, मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए मायावती

का बसपा की ओर झुकाव अखिलेश के लिए कई मोर्चों पर खतरा पैदा कर सकता है। सपा का मुस्लिम वोट बैंक, जो लगभग 20% है, उसकी एकजुटता अखिलेश की ताकत रही है। लेकिन आजम जैसे प्रभावशाली नेता का साथ



छूटना पश्चिमी यूपी की सीटों पर सपा के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जहां मुस्लिम और दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। रामपुर और मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों में आजम का प्रभाव अभी भी कायम है, और अगर वे बसपा के साथ जाते हैं, तो यह मायावती को मुस्लिम-दलित गठजोड़ बनाने में मदद कर सकता है।

अखिलेश यादव ने 2024 में अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के दम पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन उपचुनावों में सपा की हार ने संकेत दिया कि मुस्लिम वोटों में संघ लग सकती है। मायावती का मुस्लिम वोटों पर फोकस और आजम खान का संभावित समर्थन सपा के इस कोर वोट बैंक को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा, मायावती की ओर से सपा पर दलित और मुस्लिम वोटों को गुमराह करने के आरोप सियासी तनाव को और बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर, अखिलेश इस चुनौती का जवाब देने के लिए



दलित और ओबीसी नेताओं को सपा में शामिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आजम खान बसपा के साथ चले गए, तो अखिलेश को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। 2027 का चुनाव यूपी की सियासत का नया अध्याय लिखेगा, जहां मायावती और अखिलेश की रणनीतियां एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। वैसे बसपा सुप्रीमो

मायावती और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के बीच गठजोड़ की सुगबुगाहट भी तेज चल रही है। दोनों का मकसद दलित और मुस्लिम वोटों को एकजुट कर भाजपा और सपा-कांग्रेस गठबंधन को टक्कर देना है। मायावती का दलित समुदाय पर मजबूत आधार है, जबकि ओवैसी मुस्लिम समुदाय में गहरी पैठ रखते हैं। यह गठजोड़ पिछड़ा, दलित, मुस्लिम (पीडीएम) के तहत पश्चिमी यूपी और बिहार में खासा प्रभावी हो सकता है। हालांकि, यह राह आसान नहीं होगी। 2019 में मायावती ने ओवैसी पर मुस्लिम नेतृत्व को अछूत मानने का आरोप लगाया था। वहीं, ओवैसी ने कट्टरता फैलाने का दोषी ठहराया था। फिर भी, बदलते राजनीतिक माहौल में दोनों नेताओं को एकजुट होने का मौका दिख रहा है। यदि यह गठबंधन बनता है, तो यह यूपी की सियासत में भूचाल ला सकता है। यह सेक्युलर वोटों को बांट सकता है, जिससे भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ भी मिल सकता है। ●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।



केशव मोर्य के सहारे भाजपा का ओबीसी दांव

संगठन और सत्ता के संतुलन से 2027 की तैयारी

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहा मंथन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में पार्टी को मिले अपेक्षाकृत कमजोर जनादेश के बाद संगठन के पुनर्गठन की जरूरत महसूस की जा रही है। राज्य में अब तक भूपेंद्र चौधरी के बाद किसी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो सकी है और इस विलंब को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में सवाल भी उठने लगे हैं। इस बीच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्य की बढ़ती सक्रियता, दिल्ली में लगातार शीर्ष नेताओं से

मुलाकातें और ओबीसी समीकरण को लेकर उनका नाम चर्चा के केंद्र में आ गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में

में यह संख्या घटकर 36 रह गई। इसमें भी भाजपा अकेले 33 सीटें जीत पाई, जबकि सपा-कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटों पर कब्जा



जमाकर स्पष्ट संकेत दे दिया कि विपक्ष की सामाजिक रणनीति ने भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाई है। खासतौर पर ओबीसी और दलित समुदाय के मतदाताओं का झुकाव सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले की ओर गया। ऐसे में भाजपा के रणनीतिकारों को यह समझ में आ गया है कि यदि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत की हैट्रिक बनानी है, तो संगठन को फिर से सशक्त करना होगा। यही वजह है कि पार्टी अब ऐसा चेहरा तलाश रही है,

चिंताजनक रहा। जहां 2019 में भाजपा ने सहयोगियों सहित 64 सीटें जीती थीं, वहीं 2024

संगठन को फिर से सशक्त करना होगा। यही वजह है कि पार्टी अब ऐसा चेहरा तलाश रही है,

जो न सिर्फ संगठनात्मक अनुभव रखता हो, बल्कि सामाजिक समीकरणों को साधने में भी सक्षम हो। इस समीकरण में सबसे उपयुक्त नाम एक बार फिर उभर कर आया है केशव प्रसाद मोर्य का। 8 जुलाई को केशव प्रसाद मोर्य की दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकातों ने चर्चाओं को हवा दी। यह मुलाकातों केवल शिष्टाचार नहीं मानी जा रही हैं,

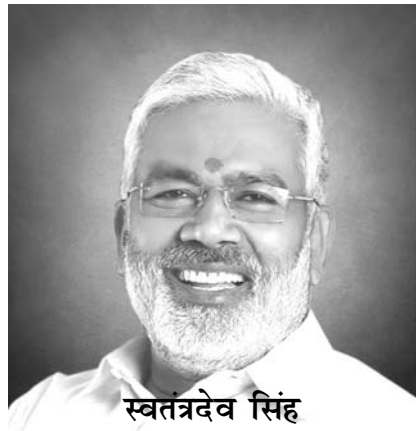
बल्कि इन्हें संगठन के पुनर्गठन और आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। खुद केशव मोर्य ने इस बात की पुष्टि की है कि इन बैठकों में 2027 की जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। यह वही केशव मोर्य हैं, जिनके नेतृत्व में 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 में से 312 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। उस समय वे प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम किया



नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। केशव मोर्य का नाम भाजपा के लिए इस समय और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि पार्टी को एक बार फिर ओबीसी समुदाय को अपने साथ मजबूती से जोड़ना है। भाजपा को अच्छी तरह से यह एहसास हो चुका है कि विपक्ष, खासकर सपा, ओबीसी वोट बैंक को खींचने की पूरी कोशिश में है। अखिलेश यादव ने पीडीए

था। मोर्य की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे भाजपा के मूल कार्यकर्ता रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से होते हुए पार्टी की मुख्यधारा में आए। उनका व्यक्तित्व एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर उपमुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले नेता का है, जो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि संगठन को फिर से सक्रिय और ऊर्जावान बनाने के लिए उनके

फार्मूले को जिस तरीके से पेश किया है, उसमें ओबीसी और दलित वर्ग को प्रमुखता दी गई है। ऐसे में भाजपा को जवाब उसी अंदाज में देना होगा। और यह काम केशव मोर्य जैसे कद्दावर ओबीसी नेता ही कर सकते हैं, जिनकी सामाजिक स्वीकार्यता व्यापक है। हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष पद पर फैसला केवल सामाजिक समीकरणों के आधार पर नहीं लिया जाएगा। इसके पीछे संगठन और सत्ता के बीच संतुलन की भी बड़ी भूमिका



स्वतंत्रदेव सिंह



बाबूराम निषाद



धर्मपाल सिंह लोधी



अमर पाल मोर्य



बेबी रानी मोर्य



वी.एल. मोर्य



दिनेश शर्मा



लक्ष्मीकांत बाजपेयी



जितिन प्रसाद

है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को 2027 में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में दोबारा प्रोजेक्ट किया जाना तय है। लेकिन समय-समय पर पार्टी के अंदर से ऐसी आवाजें उठती रही हैं कि केशव मोर्य को भी सीएम पद का दावेदार घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे में पार्टी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि मोर्य को संगठन में लाकर उन्हें सत्ता की दौड़ से बाहर रखा जाए, ताकि योगी आदित्यनाथ का रास्ता साफ रहे। इस पूरी रणनीति के पीछे केंद्रीय नेतृत्व की सोच यह है कि पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए, जो न सिर्फ सामाजिक समीकरणों को साधे बल्कि संगठन को भी धार दे। और इस पैमाने पर केशव मोर्य खरे उतरते हैं। यही कारण है कि अमित शाह ने हाल ही में एक कार्यक्रम में मोर्य को 'प्रिय मित्र' कहकर संबोधित किया, जबकि योगी आदित्यनाथ को 'लोकप्रिय मुख्यमंत्री' बताया। यह संकेत है कि पार्टी नेतृत्व दोनों नेताओं को संतुलित रूप से आगे बढ़ाना चाहता है। इस बीच भाजपा के भीतर और भी कई नामों पर विचार किया जा रहा है। ओबीसी वर्ग से स्वतंत्रदेव सिंह, अमर पाल मोर्य, धर्मपाल सिंह लोधी, बीएल मोर्य और बाबूराम निषाद के नाम चर्चा में हैं। वहीं दलित समुदाय से बेबी रानी मोर्य का नाम भी सामने आया है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत बाजपेयी और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के नामों पर विचार हो रहा है। यदि पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना चाहती है, तो जितिन प्रसाद और महेश शर्मा जैसे नेता विकल्प हो सकते हैं। हालांकि भाजपा की रणनीति यह भी रही है कि पार्टी आमतौर पर उन नेताओं को अहम पद देती है, जिनका नाम सार्वजनिक रूप से ज्यादा चर्चा

में नहीं होता। हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की नियुक्तियों ने यही साबित किया है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि मोर्य का नाम ही फाइनल है, लेकिन यह जरूर है कि वे इस रेस में सबसे आगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. दिनेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि पार्टी की एक तय प्रक्रिया होती है। पहले सभी प्रदेश इकाइयों के चुनाव कराए जाते हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होती है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब प्रदेशों में लगभग चुनाव हो चुके हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति किसी भी समय हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर देरी के पीछे चार प्रमुख कारण माने जा रहे हैं पहला, नया अध्यक्ष किस जाति या वर्ग से होगा; दूसरा, क्या वह पूर्वांचल से होगा या पश्चिम यूपी से; तीसरा, क्या वह विपक्ष के

पीडीए समीकरण को तोड़ पाएगा; और चौथा, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस नाम से सहज होंगे। सूत्रों की मानें तो पार्टी इन चारों सवालों पर गहन मंथन कर रही है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। अभी तक पार्टी की रणनीति यही रही है कि 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए संगठन को पहले से तैयार किया जाए। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पार्टी जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। लेकिन यह भी सच है कि संगठनात्मक स्तर पर खालीपन लंबे समय तक नहीं चल सकता। कार्यकर्ताओं को दिशा देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बेहद अहम होती है। और यही वजह है कि अब पार्टी पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह जल्द से जल्द इस नियुक्ति को अंतिम रूप दे। अगर केशव मोर्य को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो भाजपा एक साथ कई निशाने साध सकेगी एक, संगठन को अनुभव और जनाधार से लैस नेतृत्व मिलेगा; दो, ओबीसी समाज को संदेश जाएगा कि पार्टी उनके भरोसे पर कायम है; और तीन, सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बना रहेगा, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को चुनौती नहीं मिलेगी। अब सबकी निगाहें दिल्ली पर हैं, जहां से भाजपा के बड़े फैसले होते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा एक बार फिर केशव मोर्य पर भरोसा जताएगी या किसी नए चेहरे को सामने लाकर चौंकाएगी। लेकिन इतना तय है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भाजपा की 2027 की रणनीति का पहला बड़ा संकेत होगी। और संभव है कि यह संकेत संगठन में नई ऊर्जा और विपक्ष को सीधी चुनौती देने की दिशा में पहला कदम हो। ●



योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी की सरस्ती से यूपी छोड़ रहे हैं दिग्गज ब्यूरोक्रेट्स



अभिषेक प्रकाश

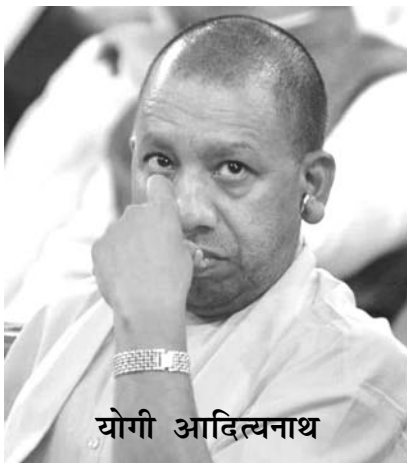


दवेन्द्र कुमार पाण्डेय

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रशासनिक तंत्र हमेशा चर्चा में रहा है। योगी सरकार की कार्यशैली, जिसमें सख्ती और जवाबदेही पर जोर है, ने न केवल नीतिगत फैसलों को प्रभावित किया, बल्कि ब्यूरोक्रेसी के ढांचे और अधिकारियों की भूमिका को भी नया आकार दिया। पिछले कुछ वर्षों में कई दिग्गज भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों से हटाकर कम प्रभावशाली भूमिकाओं में भेजा गया, जिसे नौकरशाही हलकों में हाशिए पर धकेलने के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही, सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और लगातार प्रशासनिक फेरबदल ने यूपी की ब्यूरोक्रेसी को एक नया चेहरा दिया है।

गौरतलब हो 2022 में सत्ता हासिल करते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक अधिकारियों पर सख्त नजर आये थे और यह सिलसिला आज तक जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली में नौकरशाहों से त्वरित परिणाम और पारदर्शिता की अपेक्षा रही है। इस कारण कई वरिष्ठ आईएएस



योगी आदित्यनाथ

अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटाया गया। उदाहरण के लिए, 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को 2025 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति का हिस्सा थी। अभिषेक प्रकाश जैसे अधिकारियों का निलंबन न केवल उनके करियर पर प्रभाव डालता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि सरकार किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी तरह, 2011

बैच के आईएएस अधिकारी देवेन्द्र कुमार पांडेय, जो उन्नाव में जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत थे, को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया। हालांकि, बाद में उनकी बहाली हुई, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों ने उनकी प्रशासनिक छवि को प्रभावित किया। वैसे प्रशासनिक हलकों में यह भी चर्चा छिड़ी रहती है कि योगी जी के राज में एक खास बिरादरी के अधिकारियों पर ज्यादा विश्वास जताया जा रहा है, भले ही उनकी छवि साफ सुथरी नहीं हो। वैसे ऐसे ही आरोप विपक्ष के नेताओं खास कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लगाते रहे हैं कि योगी सरकार में क्षत्रियवाद बुरी तरह से हावी है।

वैसे यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले साल एक समाचार पत्र में रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार यूपी में अपर मुख्य सचिव (एसीएस) स्तर के 16 स्वीकृत पदों में से केवल 11 पर ही अधिकारी तैनात थे। इसी तरह, प्रमुख सचिव स्तर पर 36 में से 29 और सचिव स्तर पर 96 में से 58 अधिकारी ही कार्यरत थे। कुल मिलाकर, यूपी में 652 आईएएस अधिकारियों की जरूरत के मुकाबले केवल 560 अधिकारी उपलब्ध हैं। इस कमी का एक कारण यह भी माना जाता है



भुवनेश कुमार



निवेदिता शुक्ला वर्मा



प्रणाता एश्वर्या



कामरान रिजवी



आलोक यादव



अमनदीप डुली



प्रणय सिंह

कि कई वरिष्ठ अधिकारी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। 1989 बैच के भुवनेश कुमार चतुर्वेदी केंद्रीय कृषि विभाग में सचिव बनकर चले गए, जबकि 1991 बैच के कामरान रिजवी और निवेदिता केंद्र में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं। कुछ नौकरशाही हलकों में यह चर्चा है कि योगी सरकार की सख्त कार्यशैली के कारण कई अधिकारी केंद्र की नौकरी को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे यूपी में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी और गहरा रही है।

प्रशासनिक फेरबदल योगी सरकार की एक और विशेषता रही है। हाल के वर्षों में सैकड़ों आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसी वर्ष 22 पीसीएस अधिकारियों को प्रोन्नति देकर आईएएस बनाया गया, जिन्हें जल्द ही नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इनमें से कुछ को जिलाधिकारी के पद पर तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा, 2024 और 2025 में कई बड़े पैमाने पर तबादले हुए, जिनमें 5 से 15 आईएएस अधिकारियों को एक साथ बदला गया। सितंबर 2024

में प्रनत ऐश्वर्य को मुख्य विकास अधिकारी अबेडकरनगर से विशेष सचिव नमामि गंगे और संयुक्त प्रबंध निदेशक जल निगम ग्रामीण बनाया गया। इसी तरह, उमेश प्रताप सिंह को भूतत्व खनिकर्म विभाग से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में स्थानांतरित किया गया। इन तबादलों को सरकार की कार्यकुशलता बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कई बार इन्हें अधिकारियों को हाशिए पर धकेलने के रूप में भी व्याख्या की जाती है। कई मामलों में, अधिकारियों को कम महत्वपूर्ण विभागों या पदों पर

भेजा गया, जिसे नौकरशाही में डिमोशन के रूप में देखा जाता है। लखीमपुर खीरी में खेत की पैमाइश में देरी के एक पुराने मामले में 2024 में आईएएस अधिकारी घनश्याम सिंह सहित तीन पीसीएस अधिकारियों को निलंबित किया गया। हालांकि, घनश्याम सिंह को बाद में बहाल कर लिया गया, लेकिन इस तरह की कार्यवाइयां अधिकारियों की छवि और प्रभाव को कम करती हैं। इसी तरह, 2015 बैच के कुछ अधिकारियों को जिलाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों की रेस में

अधिकारियों का निलंबन, और लगातार तबादले, ने नौकरशाही में एक तरह का दबाव बनाया है। कुछ अधिकारी इसे सरकार की सख्ती के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने की रणनीति मानते हैं। इसके बावजूद, यह स्पष्ट है कि योगी सरकार की प्राथमिकता कार्यकुशलता और पारदर्शिता है, जिसके लिए वह किसी भी स्तर पर समझौता करने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर, सरकार की योजनाओं को लागू करने में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका अहम रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, और मुफ्त बस सेवा जैसी पहलें नौकरशाही के सहयोग से ही संभव हुई हैं। लेकिन इन योजनाओं को लागू करने में विफलता या देरी ने कई अधिकारियों को सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कुंभ मेला 2025 की तैयारियों के लिए विजय किरन आनंद जैसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं, जबकि कुछ अन्य को कम प्रभावशाली भूमिकाओं में रखा गया। बहरहाल, यूपी की ब्यूरोक्रेसी



शामिल होने के बावजूद कम प्रभावशाली भूमिकाओं में रखा गया। सूत्रों के अनुसार, प्रणय सिंह, अमनदीप डुली और आलोक यादव जैसे अधिकारियों को जल्द ही जिलाधिकारी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक उनकी तैनाती अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण पदों पर ही रही है।

योगी सरकार की नीतियों ने ब्यूरोक्रेसी में जवाबदेही को बढ़ावा दिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई दिग्गज अधिकारियों को हाशिए पर जाने का सामना करना पड़ा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाइयां, जैसे 11 आईएएस

में बदलाव का यह दौर न केवल प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित कर रहा है, बल्कि अधिकारियों के करियर पथ को भी नया आकार दे रहा है। योगी सरकार की सख्ती और लगातार फेरबदल ने कई दिग्गज आईएएस अधिकारियों को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन यह भी सच है कि इस प्रक्रिया ने नए और ऊर्जावान अधिकारियों को मौका दिया है। कुल मिलाकर, यूपी की ब्यूरोक्रेसी एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां जवाबदेही और परिणाम सरकार की प्राथमिकता बने हुए हैं। ●



महुआ को रौशन कर रहे डॉ. मुकेश कुमार रौशन

राजद के 'छात्र युवा संसद' कार्यक्रम में दिखा महुआ विधायक का जलवा

● सोनू यादव

य

ह सच है कि राष्ट्र और समाज के निर्माण में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो

या फिर राजनीति का। हर राजनेता कही न कही छात्र जीवन में ही राजनीति गुण को सीख लेता है। अध्ययन के दौरान राजनीतिक शास्त्र का विषय भी इसी कारण छात्रों को पढ़ाई जाती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी राजनीतिक दल या नेता बिना युवा छात्रों के राजनीतिक मंच संभाल सकता है। ऐसे में युवा छात्रों को लेकर आगे का चुनावी सफर तय करने की दिशा में राष्ट्रीय जनता दल ने 27 जून को पटना के बापू सभागार में छात्र युवा संसद कार्यक्रम का वृहत आयोजन किया। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ ही युवा छात्रों के दिल की धड़कन पूर्व उपमुख्यमंत्री बिहार व राजद नेता तेजस्वी यादव ने उन तमाम युवा छात्रों का तहे दिन से धन्यवाद दिया, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों, कस्बों से इस कार्यक्रम में शिरकत करने आये थे। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार में आने पर बड़े और क्रांतिकारी बदलाव होंगे।

उन्होंने कहा कि जनता ने बीते बीस वर्षों में जिस सरकार को मौका दिया, उसने बिहार को पिछड़ने के अलावा कुछ नहीं दिया। अगर आरजेडी को सिर्फ बीस महीने मिल जाएं, तो वह करके दिखाएंगे जो इन बीस सालों में नहीं हुआ।

बहरहाल, राजधानी पटना का बापू सभागार युवा छात्रों से उचाठक भरा था। 'छात्र युवा संसद' के इस सफल कार्यक्रम को बनाने में पार्टी के विभिन्न जिला के विधायकों व नेताओं को जाता है। वही बता दें कि कार्यक्रम



को बेहतर बनाने की दिशा में वैशाली के महुआ विधायक डॉ० मुकेश कुमार रौशन का योगदान भी सराहनीय दिखा। विधायक डॉ० मुकेश कुमार रौशन ने कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के युवा छात्रों के लिए अपने आवास पर भोजन का प्रबंध कर रखा था। वैसे महुआ के माननीय विधायक के बारे में लोग कहते हैं कि उनके आवास पर जो भी आगतुक जाते हैं, उन्हें वह बिना भोजन कराये वापस नहीं जाने देते। उनका यह स्वभाव प्रशंसनीय है। बता दें कि कार्यक्रम को लेकर पूर्व से की गई तैयारियों में व्यस्त दिखे डॉ० मुकेश कुमार रौशन ने अपने सैकड़ों युवा छात्र साथियों को लेकर विशाल रैली के साथ राजधानी पटना के बापू सभागार पहुंचे थे। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और ईमानदारी उनके नाम के अनुरूप दिखती है। यूं कहे कि डॉ० मुकेश कुमार रौशन से महुआ की जनता रौशन, पार्टी रौशन और कार्यक्रम में आये युवा छात्र व नेता रौशन हुए, तो कहना गलत नहीं होगा।

गौरतलब है कि 12 मई 1985 को डॉ० मुकेश कुमार रौशन का हाजीपुर में जन्म हुआ। उनके पिता रामदेवन राय एक चर्चित नेता थे। 90 के दशक में जब आरजेडी सुप्रिमो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे, उस समय रामदेवन



राय उनके खास में गिने जाते थे। बहरहाल, 6 मार्च 1993 को डॉ० मुकेश कुमार रौशन के पिता रामदेवन राय की हत्या हाजीपुर के स्टेशन चौक के पास कर दी गई थी। सूत्र बताते हैं कि इस हत्या के बाद उनके भाई ने कई नामजद पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिनमें एक नाम भाजपा के वरिष्ठ नेता व वर्तमान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का भी था। बता दें कि रामदेवन राय की हत्या की जांच कभी भी ईमानदारी से नहीं हुई और मामले को लटकया जाता रहा। बाद में विधानसभा में हंगामे के बाद उस वक्त की वैशाली एस.पी. रही शोभा अहोतकर जो एक चर्चित आईपीएस हैं ने केश की फाइलों को ओपेन करवाया और धीरे-धीरे कुछ अभियुक्त पकड़े भी गये, हालांकि बाद में सारे अभियुक्त कोर्ट से बरी होते गये। आज तक यह गुत्थी सुलझी नहीं की हत्या क्यों हुई और किसने करायी? हालांकि इस हत्या में कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा का भी नाम आया था, जिसने हत्या को अंजाम दिया था पर वह भी इस केश में बरी हो गया। ज्ञात हो कि जिस वक्त रामदेवन राय की हत्या की गई थी, उस

वक्त मुकेश रौशन महज दस वर्ष के आसपास थे। संघर्ष करते हुए अपनी ईमानदार छवि और

रौशन ने आगे का सफर तय किया।

गौरतलब है कि मुकेश रौशन डेंटल सर्जन के साथ ही एक सफल व्यवसायी और समाजसेवी भी के रूप में अपनी पहचान बनायी। जनता के बीच उनकी निष्ठा और निःस्वार्थ सहयोग ने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ क्षेत्र पर जीत का परचम लहराते हुए आज वह राष्ट्रीय जनता दल के महुआ विधानसभा के सदस्य बने। विधायक बनने के बाद डॉ० मुकेश कुमार रौशन द्वारा क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर विधानसभा में हमेशा आवाज उठाते देखा गया है। ज्ञात हो कि कोविड के दौरान महुआ वासियों के लिये कोरोना महामारी से बचाव हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 50 लाख रुपये की अनुशंसा की गई थी। जिनमें कोविड महामारी से लोगों को जीवन रक्षा के अति महत्वपूर्ण कार्य हेतु 50 ऑक्सीजन गैस सिलेन्डर, 2 वेंटिलेटर मशीन, 25 बेड का आईसीयू, 1 एम्बुलेंस तथा 25 पल्स

मुकेश कुमार रौशन
सदस्य
बिहार विधान सभा
126, महुआ।

—: विचार —
साई विमला
(अनारमिटर, हाजीपुर)
मो- 9934466447,
9934460447
drmkeshraushan@gmail.com

पत्रांक : 42/अ.स.
दिनांक : 27/04/2021

जिला पदाधिकारी
वैशाली।

कोविड महामारी से लोगों को जीवन रक्षा के अति महत्वपूर्ण कार्य हेतु

1. ऑक्सीजन गैस सिलेन्डर- 50
2. वेंटिलेटर मशीन- 02
3. आई.सी.यू. बेड- 25
4. एम्बुलेंस- 01
5. पल्स ऑक्सीमीटर- 25

के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत COVID-19 मरीजों के चिकित्सा सुविधा के लिए विधायक निधि से 50 लाख रुपये की राशि इस महामारी के आपदा में चिकित्सा उपकरण क्रय हेतु खर्च की अनुशंसा करता हूँ। शीघ्र ही उपरोक्त कार्य की पूर्णतः आशा और अपेक्षा भी है।

भवदीय
[Signature]
(डा० मुकेश कुमार रौशन)
सा.वि.स.
महुआ, 126





योजना अंतर्गत कोविड-19 मरीजों के चिकित्सा सुविधा के लिए विधायक निधि से 50 लाख रुपये की राशि इस महामारी के आपदा में चिकित्सा उपकरण क्रय हेतु खर्च की अनुशंसा की गई थी। इसके अलावे यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम लहराने वाले वैशाली जिले के दो छात्रों से मिलकर महुआ विधायक डॉ० मुकेश कुमार रौशन ने दोनों छात्रों को अंगवस्त्र एवं फूल माला से सम्मानित किया था। विधायक ने छात्रों को मुंह मीठा करा कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की थी। उन्होंने कहा कि हमारे जिले के लिए गर्व की बात है। शिक्षा वह अनमोल रत्न है जो पढ़ेगा वह किसी भी सफलता को हासिल करेगा। बच्चों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। माता-पिता के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संस्कार देने के कारण ही आज इनके बच्चें देश विदेश में नाम का रोशन कर रहे हैं। वहीं महुआ विधायक डॉ० मुकेश रौशन ने विधानसभा में हाजीपुर-महुआ-मुजफ्फरपुर एसएच को एनएच में परिवर्तित करने की अवाज उठाई और इस सड़क को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री से अपनी बात रखने को कहा। इस दौरान मंत्री ने सदन में इस दिशा में सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिया। सभापति ने भी मंत्री के जबाब को सकारात्मक बताते हुए कार्यवाही आगे बढ़ाया। विधायक डॉ०

रौशन ने बताया कि महुआ में जाम की समस्या दूर करने के लिए सदन में आवाज उठाई है। हाजीपुर-महुआ-मुजफ्फरपुर स्टेट हाईवे को एनएच में परिवर्तन के लिए भारत सरकार के समक्ष राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजने की मांग की गई है। साथ ही इन दोनों सड़कों को फोर लेन



बनाने का प्रस्ताव भी दिया। ताकि महुआ में हर दिन लगने वाले जाम से महुआवासियों को मुक्ति मिल सके। विधायक ने बताया कि मेरे प्रयास से पिछले महागठबंधन की सरकार में तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने महुआ में बाईपास निर्माण कार्य की स्वीकृति दी थी। कार्य पूर्ण होने के बाद महुआ के लोगों को काफी हद तक जाम से निजात मिलेगी।

बहरहाल, महुआ विधानसभा एवं अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा एवं छात्रों को साथ लेकर महुआ विधायक डॉ० मुकेश कुमार रौशन

पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने कहा कि छात्र और युवाओं के कंधों पर सवार होकर ही देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार 21वीं सदी में प्रगति और समृद्धि की उड़ान भर सकता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बुरी स्थिति और बेरोजगारी की भयावह स्थिति से एनडीए सरकार ने बिहार के भविष्य को अंधकारमय बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा है। बिहार के विद्यालयों एवं कालेजों में शिक्षकों का अभाव, पाठ्यक्रम में गुणवत्ता की कमी, पठन-पाठन को लेकर सरकार की उदासीनता, चिंतनीय, ड्राप आउट रेट इत्यादि समस्याएं बिहार के छात्रों को घेरे हुए हैं। वहीं हर परीक्षा में पेपर लीक, धांधली, कालेज में सेशन लेट चलना, नौकरी और रोजगार के अवसरों का अभाव, बिहार में पूंजी निवेश की कमी, इत्यादि समस्याओं से बिहार का युवा जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं और छात्रों को लामबंद करने तथा बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर उनके दायित्वों के प्रति उन्हें सजग बनाने हेतु राष्ट्रीय जनता दल छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया।

इस आयोजन में शामिल होने वाले सभी छात्रों एवं युवाओं के बीच कलम की ताकत पर बिहार के उत्थान को लेकर उनकी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में कलम वितरित किया गया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार के भविष्य एवं देश के युवाओं के आदर्श माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा सकारात्मक पहल तेजस्वी जी कलम बांट कर छात्र युवा क्रांतिकारी साथियों के तकदीर बदलने की बात कर रहे हैं। बिहार के लाखों युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जुमलेबाज ऑफ इंडिया एनडीए के सरकार द्वारा हथियार का लाइसेंस बांटा जा रहा है। आज छात्र-युवा संसद में उमड़े युवाओं के लिए देर सारा प्यार और आभार! बिहार के युवा 20 वर्षों की इस निकम्मी एनडीए सरकार की मंशा भाँप चुका है। युवा अब वह सत्ता के फैसले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अब सत्ता का फैसला करेगा। बिहारी युवा मिट्टी के नहीं, हौसलों और हिम्मत के बने हैं। हमारी सोच में लहू नहीं क्रांति दौड़ती है। युवा साथियों-उठो, ठानों और चलो और तब तक मत रुको, जब तक बिहार फिर से ज्ञान, कर्म, भक्ति, प्रगति और तरक्की की राजधानी न बन जाए! ●

केवल सच राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के 20 वर्षों का गौरवशाली सफर

‘शून्य से शिखर तक’ विशेषांक का भव्य विमोचन



● अमित कुमार/ मिथिलेश कुमार

हिं दी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता और विशिष्ट पहचान बनाने वाली प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका ‘केवल सच’ ने अपने प्रकाशन के 20 गौरवशाली वर्ष पूरे कर एक ऐतिहासिक पड़ाव हासिल किया है। इस अभूतपूर्व अवसर को यादगार बनाने के लिए, राजधानी पटना के प्रतिष्ठित रविन्द्र भवन में पत्रिका के 20वें स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें एक हजार से अधिक दर्शकों और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए सम्मानित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया।

➤ आर्यभट्ट को समर्पित ‘शून्य से शिखर

तक’ विशेषांक का लोकार्पण :- इस ऐतिहासिक समारोह का सबसे महत्वपूर्ण क्षण महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद् आर्यभट्ट पर केंद्रित ‘शून्य से शिखर तक’ विशेषांक का लोकार्पण रहा। यह विशेष अंक आर्यभट्ट के असाधारण जीवन, उनके युगांतरकारी आविष्कारों, विशेष रूप से शून्य की खोज और विज्ञान तथा गणित के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय योगदान को गहराई से रेखांकित करता है। यह विशेषांक न केवल आर्यभट्ट के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के उस स्वर्णिम अध्याय को भी पुनर्जीवित करता है जिसने विश्व सभ्यता को एक नई दिशा दी।

➤ गरिमामयी उपस्थिति और वक्ताओं के प्रेरक उद्बोधन :- समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और आर्यभट्ट के चित्र पर श्रद्धासुमन

अर्पित करने के साथ हुआ, जो भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के प्रति सम्मान का प्रतीक था। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रिका के दूरदर्शी संपादक और संस्थापक श्री ब्रजेश मिश्र ने की, जिनके अथक प्रयासों और प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि ‘केवल सच’ ने यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। मंच पर अनेक गणमान्य हस्तियाँ उपस्थित थीं, जिनमें पटना की यशस्वी मेयर श्रीमती सीता साहू, इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश सिंह, प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुमार, वैद्यनाथ प्रा. लि. के संस्थापक प्रमोद शर्मा, नवादा रोटरी क्लब के संस्थापक एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष समाजसेवी राजेश्वर प्रसाद राजेश, आगरा से पधारे हनुमंत भूमिया सरकार, और अयोध्या के सुदर्शनाचार्य जी महाराज आदि प्रमुख थे। इन सभी विभूतियों



की उपस्थिति ने समारोह में चार चाँद लगा दिए। वक्ताओं ने अपने उद्बोधनों में आर्यभट्ट के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनके गणितीय योगदान, और भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। भारत के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, तो कुछ नाम शाश्वत रूप से प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। वे केवल व्यक्ति नहीं, विचार होते हैं; केवल गणितज्ञ नहीं, युगद्रष्टा होते हैं। आर्यभट्ट ऐसे ही एक दिव्य प्रकाशपुंज थे, जिन्होंने न केवल भारत को वैज्ञानिक दृष्टि से समृद्ध किया, बल्कि समस्त विश्व को तार्किक चिंतन और गणनात्मक विवेक का संदेश दिया। आज जब केवलसच पत्रिका अपने 20 वर्षों की सत्यनिष्ठ पत्रकारिता का उत्सव मना रही है, और 'आर्यभट्ट केवल सच सम्मान समारोह' का आयोजन कर रही है, तब आर्यभट्ट को स्मरण करना उस परंपरा को नमन करना है, जो सत्य, विज्ञान और विवेक की बुनियाद पर टिकी है।

☞ **आर्यभट्ट: जीवन की झलकियाँ :-** आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनका जन्मस्थान विवादास्पद है। कुछ

विद्वान् केरल के तिरुवनकुर को मानते हैं, तो अधिकांश विद्वान् कुसुमपुर (आधुनिक पटना) को उनका कर्मभूमि मानते हैं। यह वही काल था जब भारत गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा था। कला, साहित्य, विज्ञान और शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित हो रही थी। आर्यभट्ट का जीवन सादगी, अध्ययन और गहन चिंतन से भरा था। ऐसा माना जाता है कि वे नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े थे। उनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है। आर्यभटीय, जो आज भी वैज्ञानिक साहित्य का अमूल्य रत्न है।

☞ **आर्यभटीय: श्लोकों में विज्ञान :-** इस अद्भुत ग्रंथ की रचना मात्र 121 श्लोकों में हुई है। किंतु इन श्लोकों में छिपे ज्ञान का विस्तार चमत्कारी है।

☞ **आर्यभटीय के चार भाग हैं :-** गीतिकपाद, कालगणना एवं खगोलशास्त्रीय मूल तथ्य गणितपाद, अंकगणित, बीजगणित, क्षेत्रमिति कालक्रियापाद, युगों की गणना, पंचांग सिद्धांत गोलपाद, ग्रहों की गति, भूगोल और ब्रह्मांड का स्वरूप।

आर्यभट्ट ने श्लोकों के माध्यम से जटिल गणनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि पाठक न केवल उसे पढ़ें, बल्कि समझें और आत्मसात करें। उनकी शैली में वैज्ञानिकता और साहित्यिकता का अद्वितीय समन्वय है।

☞ **गणित की दुनिया में क्रांति :-** आर्यभट्ट ने च (पाई) का मान 3.1416 बताया, जो आधुनिक गणना से मात्र अंशों का अंतर रखता है। उन्होंने दशमलव प्रणाली की नींव डाली और स्थानिक मान (Place Value System) को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उनकी त्रिकोणमिति तालिकाएँ और बीजगणितीय सूत्र आज भी प्रासंगिक हैं। वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त, चतुर्भुज ख सभी की गणनाएँ उन्होंने सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत कीं।

☞ **खगोलशास्त्र में नवीन दृष्टि :-** आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा 'पृथ्वी स्थिर नहीं, स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है। यही दिन-रात के परिवर्तन का कारण है।' उनके समय में यह अवधारणा अत्यंत क्रांतिकारी थी। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों को धार्मिक व्याख्या



चंद्र प्रकाश सिंह



डॉ० सुनील कुमार



राजेश्वर प्रसाद राजेश

“आर्यभट्ट केवल सच सम्मान-2025” से सम्मानित सदस्य



से हटाकर वैज्ञानिक तर्क से जोड़ा कि यह छाया और प्रकाश के कारण होते हैं, न कि शरहू-केतुश जैसे पौराणिक पात्रों से। उन्होंने सौर वर्ष की अवधि 365.358 दिन बताई ख यह आधुनिक वैज्ञानिक गणना (365.256 दिन) से अत्यंत निकट है।

☞ आर्यभट्ट की दृष्टि: ज्ञान और विवेक

का संगम :- आर्यभट्ट की महानता केवल उनके सिद्धांतों में नहीं, उनके चिंतन में थी। वे तर्क के पुजारी थे, अनुभव के माध्यम से सत्य को प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। उनके लिए ज्ञान केवल अध्ययन का विषय नहीं, आचरण का आधार था।

☞ आज के युग में आर्यभट्ट की प्रासंगिकता

:- आज जब हम सूचना और अफवाहों के शोर में घिरे हैं, सत्य और प्रमाण का महत्व पहले से कहीं अधिक है। आर्यभट्ट हमें सिखाते हैं-सोचो, गणना करो, प्रमाण दो और तभी विश्वास करो। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि भारत की वैज्ञानिक चेतना कोई आयात नहीं, बल्कि हमारी आत्मा में समाहित है।



केवल सच पत्रिका का आर्यभट्ट के नाम पर सम्मान समारोह आयोजित करना, एक वर्तमान का झुकाव है अतीत की ऊँचाई की ओर है। यह आयोजन न केवल पत्रकारिता को नई दिशा देता है, बल्कि यह बताता है कि सत्य और विवेक का मार्ग आर्यभट्ट के समय जितना आवश्यक था, उतना ही आज भी है।

❧ **विज्ञान का दीपक कभी बुझता नहीं, जो आर्यभट्ट ने जलाया, वह युगों तक राह दिखाएगा :-** डॉ. सुनील कुमार ने शून्य के आविष्कार के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, 'यदि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार नहीं किया होता, तो न तो विज्ञान होता, न तकनीक और न ही आधुनिक जीवन की संरचना।

केवल सच ने एक महान विभूति को सही मंच दिया है।' यह कथन शून्य के वैश्विक प्रभाव और आर्यभट्ट की दूरदर्शिता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ईंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश सिंह ने 'केवल सच' पत्रिका के संघर्ष और सफलता की यात्रा की सराहना करते हुए कहा, ब्रजेश मिश्र जैसे कर्मठ पत्रकारों की मेहनत का ही परिणाम है कि आज केवल सच ने दो दशक पूरे किए। आर्यभट्ट जैसे मनीषी पर आधारित यह विशेषांक नई पीढ़ी को प्रेरणा देगा। उन्होंने पत्रिका को एक विशेष सुझाव भी दिया कि पत्रिका का एक पन्ना मजदूरों की समस्याओं के लिए भी समर्पित होना चाहिए, जो पत्रिका के सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी अपेक्षा को दर्शाता है। वहीं, राजेश्वर प्रसाद राजेश ने 'केवल सच' की विश्वसनीयता पर जोर देते हुए कहा कि यह आम जनमानस की आवाज बन चुकी है। उन्होंने मीडिया के बदलते परिदृश्य पर टिप्पणी

करते हुए कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बावजूद, 'केवल सच' की खबरें आज भी लोगों के बीच भरोसा कायम रखे हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पत्रिका भविष्य में भी आम लोगों की समस्याओं, सरकार की उपलब्धियों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आक्रामक बनी रहेगी।

❧ **सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और 'केवल सच आर्यभट्ट सम्मान-2025' :-** कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी मनमोहक संगम देखने को मिला, जिसने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इंडियन आइडल



सीजन-5 के विजेता रजत ने अपनी मधुर आवाज में 'श्रीराम जानकी...' गीत से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अतिरिक्त, नन्ही बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत कृष्ण-राधा नृत्य ने सभागार में उल्लास और भक्ति का संचार किया।

समारोह का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण 'केवल सच आर्यभट्ट सम्मान-2025'

का आयोजन रहा। इस प्रतिष्ठित सम्मान के तहत, देश-प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन व्यक्तित्वों को समर्पित था, जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनकर मिसाल कायम की है और 'केवल सच' ने उन्हें एक उपयुक्त मंच प्रदान कर उनके योगदान को सराहा।

❧ **संपादक ब्रजेश मिश्र का आभार और भविष्य की प्रतिबद्धता :-** कार्यक्रम के समापन पर 'केवल सच' के संपादक श्री ब्रजेश मिश्र ने सभी दर्शकों, अतिथियों, पत्रकार साथियों, संरक्षकों और पाठकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी 20 वर्षों की यात्रा को संघर्षों से भरी बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनकी टीम, विज्ञापनदाताओं और पाठकों द्वारा दिखाए गए अटूट विश्वास के कारण ही वे इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। श्री



ब्रजेश मिश्र

मिश्र ने अपनी पत्रिका की मूल भावना को दोहराते हुए कहा, हमारी पत्रिका हमेशा उन विभूतियों को सामने लाने का कार्य करती रही है, जिन्होंने समाज में बदलाव की अलख जगाई है। यह समारोह न केवल 'केवल सच' के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, बल्कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा, विशेषकर गणित और खगोल विज्ञान में भारत के अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने का भी एक सार्थक और प्रेरणादायक प्रयास रहा। 'शून्य से शिखर तक' जैसे विशेषांक नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित

कराने और उनमें प्रेरणा जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने सभी उपस्थित लोगों को एकजुटता और राष्ट्रीय गौरव की भावना से भर दिया। वक्ताओं ने केवल सच के संघर्ष के 20 वर्ष पुरे होने पर पूरी टीम की निष्ठा और सहयोग की भावना के लिये अपनी शुभकामनायें देते हुए कहा की जब सरकार मध्यम एवं छोटी पत्रिकाओं को आर्थिक सहयोग न कर उसकी स्वतन्त्रता पर भी अंकुश लगाने का प्रयास कर रही हैं वैसे समय में भी केवल सच पत्रिका निरंतर अपनी

कर्तव्यों एवं पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए सरकार को आईना दिखाया वही अच्छे कार्यों की प्रशंसा से भरी खबरों का प्रकाशन भी करते रहा। आज 'केवल सच' देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपने प्रकाशन से सरकार एवं आम लोगों तक अपनी गहरी पैठ बना चुका है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों पत्रकार, बुद्धिजीवी, चिकित्सक, अधिवक्ता, समाजसेवी सहित हजारों लोग उपस्थित थे, जो 'केवल सच' की जन-जन तक पहुँच और उसके प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है। ●

राम अवतार मार्केट में नया चिकित्सा केन्द्र शुरू

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

राजधानी पटना से 35 किलोमीटर पर मसौढ़ी प्रखण्ड अंतर्गत हनुमान नगर स्थित राम अवतार मार्केट में मेडिमातृत्व एवं सर्जरी क्लीनिक की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जेनरल एवं कैंसर सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. पी. कुमार और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. स्वेता सिन्हा ने साध्य एवं असाध्य रोगों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। दोनों डॉक्टरों ने बताया कि बढ़ती बीमारियों के बीच समय पर जांच और सही इलाज से जटिल रोगों पर काबू पाया जा सकता है। डॉ. पी. कुमार ने कहा कि लोगों को अपनी दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी शुरूआती चरण में पकड़ में आ जाएं तो इलाज संभव है। वहीं, डॉ. स्वेता सिन्हा ने महिलाओं में बढ़ती बच्चेदानी से जुड़ी बीमारियों, डिलेवरी और सिजेरियन ऑपरेशन से संबंधित समस्याओं पर



समय पर जांच और जागरूकता से कैंसर जैसे रोगों पर काबू पाया जा सकता है।

—: डॉ. पी. कुमार, कैंसर सर्जरी विशेषज्ञ

महिलाओं की बीमारियों को लेकर अब भी झिझक है, जागरूकता से बेहतर समाधान संभव है।

—: डॉ. स्वेता सिन्हा, स्त्री रोग विशेषज्ञ



चर्चा करते हुए बताया कि ग्रामीण इलाकों में अब भी सही जानकारी की कमी से कई बार स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे में समय पर परामर्श जरूरी है। क्लीनिक के व्यवस्थापक श्रीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि मसौढ़ी जैसे अर्ध-शहरी इलाके में कम खर्च में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा शुरू की गई है, जिससे

आसपास के गांवों के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि यहां डिलेवरी, सिजेरियन, हर्निया, हाइड्रोसील, पथरी, बवासीर, भगंदर व गांठ की सर्जरी जैसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही मरीजों को इलाज के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ●

भाजपा, जदयू के लिए रोड़ा बनेंगे चिराग पासवान

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। चिराग का लक्ष्य पार्टी के पिछले गौरव को बहाल करना और मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान की अगुवाई वाले लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 243 सीटों पर उम्मीदवार के घोषणा से भाजपा और जदयू सदमे में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ने पर संव्यं नुकसान किया था परंतु नीतीश कुमार को 43 सीट पर सिमटा दिया। चिराग पासवान ने इस बार 243 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर



दी है। ऐसी स्थिति में इस बार जदयू का 43 से

भी कम पर सीट पर सिमट जाने का स्थिति बनते जा रही है। बताया जाता है कि पिछले बार बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री तक को अथक प्रयास करने के बावजूद भी भाजपा 74 सीटों पर सिमट गई थी। पिछली बार भाजपा ने नीतीश कुमार को सत्ता सौंप कर भारी भुल की थी। भाजपा को बाहर से समर्थन कर भ्रष्टाचार और अपराध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 243 सीटों पर घोषणा कर दिया है। ऐसे स्थित कायम रहा तो भाजपा 50 से भी कम सीटों पर सिमट सकती है। जिसका मुख्य कारण है कि भाजपा शहरों का शोभा के वस्तु बन कर रह गई है। समुचे बिहार अपराध के नगरी, भ्रष्टाचार के साम्राज्य होने के बावजूद झूठे जीरो टॉलरेंस के नारा लगाने में इतना व्यस्त रहा कि गरीबों के लिए जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को घर घर नहीं पहुँचाया। ●

फतुहा में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का आयोजन

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता तथा चिकित्सकों को सम्मानित भी किया जाता है। फतुहा में डॉ० राजीव कुमार विनायक डेंटल अस्पताल के द्वारा राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया गया। चिकित्सकों ने कहा कि त्याग, समर्पण और सभी को स्वास्थ्य बनाए रखने के जुनून को सम्मान करने के लिए मनाते हैं। चिकित्सक के विना जीवन का कल्पना करना मुश्किल लगता है यही वजह है कि डॉक्टरों को धरती का भगवान का दर्जा दिया जाता है।

कोरोना काल में इलाज के क्रम में बहुत से चिकित्सक को अपना जीवन भी गवाना पड़ा। भारत सरकार द्वारा पहला राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस साल 1991 में मनाया गया था। 1 जुलाई 1882 को जन्मे डॉक्टर बिधान चंद्र राय एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। चिकित्सक के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस घोषित किया। डॉक्टर राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 1 जुलाई



1962 के दिन ही डॉक्टर बिधान चन्द्र राय का निधन हो गया था। डॉ० राजीव ने कहा कि यह दूसरा बार मनाया जा रहा है। डॉ० राजीव जी को इस भव्य आयोजन के लिए उपस्थित सभी लोगों ने बधाई दी। शामिल चिकित्सकों में डॉ० मुकेश रोशन विधायक, डॉ० राजेंद्र कुमार, डॉ० वैभव शांडिल्य, डॉ० राहुल मिश्रा, डॉ० उमेश प्रसाद, डॉ० ब्रजमोहन प्रसाद, डॉ० संजय प्रसाद, डॉ०

गोपाल जी, डॉ० रंजीत कुमार, डॉ० स्वामी, डॉ० सुधीर कुमार, डॉ० विभूतिभूषण, डॉ० विजय यादव, डॉ० अभिषेक, डॉ० ओम प्रकाश, डॉ० मधुबाला, डॉ० सुशील पोद्दार, डॉ० विनय कुमार, डॉ० राज किशोर, डॉ० अनिल प्रकाश, डॉ० श्याम, डॉ० संजय कुमार सिंह, डॉ० गोविंद चौधरी, डॉ० पूजा वर्मा, डॉ० लक्ष्मी नारायण सिंह आदि सैकड़ों चिकित्सक शामिल हुए। ●